वर्ष : 01 अंक : 11 जून, 2026 पृष्ठ : 36 RNI No. UPHIN/25/A0721 मूल्य : 20

हिन्दी मासिक पत्रिका

पॉलिटिकल इमेज



योगी के सहयोगी



12 भोजशाला वाग्देवी का मंदिर



दिलकुशा

नवाबी दौर की दिलकुशा कोठी गोमती नदी के तट पर स्थित है।इस कोठी को गॉथिक शैली में बनाया गया था। दिलकुशा कोठी लखनऊ के दिलकुशा क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस इमारत की वास्तुकला डिजायन में इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रलैंड के सिटॉन डेलावल हॉल के पैटर्न की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसे वास्तव में नवाबों के शिकार लॉज के रूप में बनवाया गया था लेकिन बाद में इसे गर्मियों में रहने वाले घरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा।



संपर्क करें

महानिदेशक पर्यटन : पर्यटन निदेशालय , उत्तर प्रदेश, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पर्यटन भवन,सी-13, विपिन खंड, गोमती नगर,लखनऊ, उत्तर प्रदेश

फोन नं : +91-522-4061369, ईमेल : dg-upt@up.gov.in// बुकिंग/ टूर पैकेज से सम्बंधित जानकारी हेतु संपर्क करें - 0522- 4004402, 2612659

पॉलिटिकल इमेज

वर्ष : 01 अंक : 11 जून, 2026

पृष्ठ : 36 मूल्य : 20

सम्पादक

गरिमा सिंह

स्वामी, प्रकाशक गरिमा सिंह एवं मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41/381 नरही, लखनऊ, ऊ.प्र.-226001 से मुद्रित व सी- 62, इन्दिरा नगर, लखनऊ, ऊ.प्र.-226016 से प्रकाशित।

सम्पादक - गरिमा सिंह

RNI No. UPHIN/25/A0721

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

e-mail

singsgarima@gmail.com

Phone : 8595476939

इस अंक में



03

भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय बने मंत्री



18

तपती गर्मी के बीच बर्फ का आनंद



22

सनातन विरोध की राजनीति पर जनता का लोकतांत्रिक प्रहार



32

यमुनोत्री शुद्धि, गंगोत्री कृपा, केदारनाथ पश्चाताप

बद्रीनाथ का संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से है

सम्पादक की कलम से...



गरिमा सिंह
सम्पादक

जीवन की लय तय करती है 'मोरल साइंस'

पुराने समय में, स्कूलों में 'मोरल साइंस' (नैतिक विज्ञान) नामक एक विषय होता था और सुबह की सभाएं अक्सर राष्ट्रगान और एक सरल भजन के साथ शुरू होती थीं। ये केवल अनुष्ठान नहीं थे, इन्होंने युवा दिमागों को आकार देने में एक शांत लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाई। आज की जटिल, डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे बच्चों के लिए इन प्रथाओं को वापस स्कूलों में लाना गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

मोरल साइंस कभी भी परीक्षा या ग्रेड के बारे में नहीं थी। यह एक अच्छा इंसान बनने के बारे में थी। सरल कहानियों, चर्चाओं और उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को ईमानदारी, दया, सम्मान, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ देने और सांझा करने की कला सिखाई जाती थी। ये सबक उस समय छोटे लग सकते थे लेकिन वे जीवन भर छात्रों के साथ रहे। उन्होंने बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद की, डर के कारण नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के कारण। आज के बच्चे बहुत अलग माहौल में बड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया उनके दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जहां यह ज्ञान और जुड़ाव प्रदान करता है, वहीं उन्हें नकारात्मकता, हिंसा, बदमाशी, अवास्तविक जीवनशैली और निरंतर तुलना के संपर्क में भी लाता है। युवा दिमाग अभी विकसित हो रहे हैं और वे जो देखते और सुनते हैं, उससे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना, उनके लिए इन प्रभावों को स्वस्थ तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है।

यही वह जगह है जहां मोरल साइंस फिर से बदलाव ला सकती है। यह उन्हें साथियों के दबाव को संभालने, असफलता से निपटने और बिना अहंकार के आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर सकती है। यह उन्हें सिखाता है कि सफलता केवल जीतने के बारे में नहीं, बल्कि निष्पक्ष, दयालु और ईमानदार होने के बारे में भी है। सुबह की सभाएं भी दिन की लय तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिन की शुरुआत राष्ट्रगान या वंदे मातरम या किसी देशभक्ति गीत के साथ करने से एकता और अपनेपन की भावना पैदा होती है। यह छात्रों को याद दिलाता है कि वे अपने आप से बड़ी किसी चीज (अपने देश) का हिस्सा हैं। यह जबरदस्ती नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास के माध्यम से सम्मान और गर्व की भावना जगाता है। भजन या एक साधारण भक्ति या प्रेरणादायक गीत जोडने से युवा दिमागों में शांति और एकाग्रता आ सकती है। विचार एक शांतिपूर्ण क्षण बनाने का है, जहां बच्चे अपना शैक्षणिक कार्य शुरू करने से पहले रुकें, सांस लें और सकारात्मक विचारों से जुड़ें। ऐसी दुनिया में, जहां बच्चे लगातार स्क्रीन और तेज कंटैंट से उत्तेजित रहते हैं, कुछ मिनटों का शांत चिंतन भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है।

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि स्कूलों को केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए, जो पारंपरिक या पुरानी लगती हो। लेकिन सच तो यह है कि चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा अधूरी है। एक बच्चा जो उच्च अंक प्राप्त करता है लेकिन जिसमें सहानुभूति या अखंडता की कमी है, वह वास्तविक जीवन में संघर्ष कर सकता है। दूसरी ओर, एक बच्चा जो मूल्यों को समझता है, भले ही वह पढ़ाई में औसत हो, उसके एक जिम्मेदार और संतुलित वयस्क के रूप में विकसित होने की संभावना अधिक होती है। मोरल साइंस को फिर से शुरू करने का मतलब पीछे जाना नहीं, इसका अर्थ है नींव को मजबूत करना। आधुनिक समय के अनुरूप इस विषय को अपडेट किया जा सकता है। पाठों में डिजिटल जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और दैनिक जीवन में दयालुता के महत्व जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकों की बजाय वास्तविक जीवन के उदाहरणों, समूह चर्चाओं और गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं।

पीछे मुड़कर देखने पर, कई वयस्कों को अपने स्कूल के दिन केवल पाठों और परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा सीखे गए मूल्यों, गाए गए गीतों और अनुशासन और एकजुटता की भावना के लिए याद आते हैं। इन यादों ने उन्हें वह बनाया, जो वे आज हैं। अब समय आ गया है कि आज के बच्चों को भी वही अवसर दिया जाए। यह बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने के बारे में है, न कि केवल करियर के लिए। यह उन्हें विचारशील, सम्मानजनक और जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में बढने में मदद करने के बारे में है। लंबे समय में, यही वास्तव में एक मजबूत समाज का निर्माण करता है। यदि स्कूल यह कदम उठाते हैं, तो इसका प्रभाव मार्कशीट में तुरंत या प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा लेकिन यह बच्चों के सोचने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके में दिखाई देगा। ■

भारत की विकास यात्रा



–सी.पी. राधाकृष्णन
(भारत के उपराष्ट्रपति),
26 मई, 2026।

जब मैं तिरुप्पुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में देश को लेकर कई सपने थे। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे–भारत अपनी महानता कब वापस पाएगा? विश्व मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कब उभरेगा? हमारे गरीब और वंचित भाई–बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे, वे अब साकार हो रहे हैं।

मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।' मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा, तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनकर उभरेगा। पिछले एक दशक में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है, 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे ठीक वही हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है।'

ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा आर्थिक विकास समावेशी रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। अब तक भारत में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग 04 करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने के पानी का कनैक्शन उपलब्ध कराया गया है। हमने खुले में शौच से मुक्त राष्ट्र बनने का संकल्प लिया था और केवल 60 महीनों के भीतर देश ने 60 करोड़ लोगों के लिए यह लक्ष्य हासिल कर दिखाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर वर्ष 05 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है।

हमारे किसानों ने अपनी मेहनत से 35 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन किया है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश बन गया है। भारत अब चावल उत्पादन में भी दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और अपने निर्यात के माध्यम से दुनिया से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। आज हमारी नारी शक्ति के लिए देश के विकास में पूरी भागीदारी के अवसर खुल रहे हैं। 03 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। अब महिलाएं सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन भी प्राप्त कर रही हैं और युद्धक भूमिकाओं में भी भाग ले रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा।

युवाओं के लिए पिछले 10 वर्षों में ही 13 नए आई.आई.टी. स्थापित किए गए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इसी तरह आई.आई.एम. की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो चुकी है और मैडीकल कालेजों की संख्या 37 से बढ़कर 823 हो गई है। यह

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर वर्ष 05 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है।



गर्व की बात है कि मैडीकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गई है। हम विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। देशभर में 164 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेनों ने रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत की है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है।

विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में देश ने जो प्रगति हासिल की है, वह हम सभी को गर्व से भर देती है। तकनीक से लेकर चिकित्सा तक, हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। कोविड–19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर बहुत कम समय में सभी को मुफ्त उपलब्ध कराई। भारत ने मानवीय संवेदना के साथ दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। चंद्रयान–3 की सफल लांचिंग ने भारत को उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में पहुंचा दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केंद्र बना रही हैं, जिससे निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत अब सैमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भी हमने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत आज 300 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात करने वाला देश बन चुका है।

कई दशकों तक हमारे देश ने केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि उग्रवाद और वामपंथी चरमपंथ जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है। साहसिक नीतिगत फैसलों और कानून के सख्त पालन के माध्यम से आज देश में शांति स्थापित हुई है और इन क्षेत्रों में विकास के द्वार खुले हैं। हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बने और दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में पहुंचे। कठिन परिश्रम का यह दौर ही 'अमृत काल' है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द हमें प्रेरणा देते हैं और दिशा भी दिखाते हैं, 'मेरे भाइयो, आइए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। यह सोने का समय नहीं है। भारत का भविष्य हमारे प्रयासों पर निर्भर करेगा।' ■

सोमनाथ हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है।

–नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
दिनांक–08 मई, 2026।

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता हैं। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है. तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है– 'प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्'. अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन–पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझायी नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आये और गये, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार–चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे।

लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभायी। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की।

महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा–पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर ने, जिनकी 300वीं जयंती मनायी जा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही, हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है. उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

पूरे भारत में 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना फैल रही थी. सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की



'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया हैं इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान भी बनाये रखी है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं।

नींव रखी जा रही थी. ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी– सोमनाथ की दुर्दशा। तेरह नवंबर, 1947 को दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नये उत्साह से भर दिया. दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था. इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बावजूद प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है. उनके विजन को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। वर्ष 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर उसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्तूबर, 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2001 को गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। उसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनायी जा रही थी। उस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने उसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई, 1951 को अपने भाषण में कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया हैं इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान भी बनाये रखी है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते. भारत के विभिन्न हिस्सों से आये लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता. आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक हैं।

इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जायेगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है. यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती हैं।

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब इसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई. वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखा. आप समझ पायेंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी।

वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है. मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। ■

कैबिनेट विस्तार : भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय को मिली जगह

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 10 मई को अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने का बड़ा संदेश दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में आयोजित समारोह में छह नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि दो राज्यमंत्रियों को प्रमोट किया गया। सबसे पहले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) छोड़कर भाजपा के साथ आए मनोज पांडेय को मंत्री बनाया गया। इनके अलावा, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं, राज्यमंत्री अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को प्रमोशन देकर सरकार ने संगठन और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कृष्णा पासवान ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में हम लोग और तेजी से कार्य करेंगे।

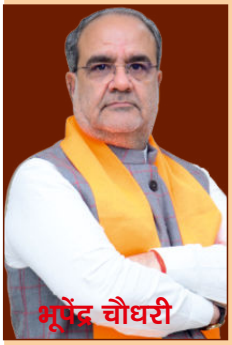
मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, तीन ओबीसी और दो दलित चेहरे शामिल किए गए हैं। सपा के प्रभावशाली ब्राह्मण नेता रहे मनोज पांडेय को मंत्रिमंडल में शामिल कर भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट राजनीति के लिहाज से भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी को भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने इस विस्तार के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सहयोगी दलों के समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास किया है।

इससे पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार 05 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। उस समय ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विस्तार से पहले योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री थे, ऐसे में छह पद रिक्त थे, जिन्हें अब भर दिया गया है। ■

मिली जिम्मेदारी

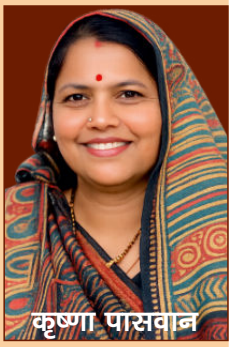
उत्तर प्रदेश में रविवार, 10 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेने वाले मंत्रियों को रविवार, 17 मई को विभाग बांट दिए गए हैं।


भूपेंद्र चौधरी


मनोज पांडेय

कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय समेत सभी मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं। श्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। अभी तक यह विभाग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के पास था। मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मिला है। सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है।


सुरेंद्र दिलेर


कृष्णा पासवान

यूपी के राजनीतिक गलियारे में इस मंत्रिमंडल विस्तार को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।


हंसराज विश्वकर्मा


कैलाश सिंह राजपूत

यूपी के पहले 'उत्कृष्ट विधायक'



उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शनिवार, 16 मई को पहली बार सदस्यों के मध्य से एक उत्कृष्ट विधायक को चयन किया है। इस बार संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री, सुरेश कुमार खन्ना को उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत गठित 'उत्कृष्ट विधायक समिति' की बैठक विधानसभा सतीश महाना की अध्यक्षता में विधान भवन में हुई।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, नामित वरिष्ठ सदस्य विधानसभा रमापति शास्त्री एवं नामित वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सदस्यों के मध्य से एक उत्कृष्ट विधायक का चयन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि विधानसभा के 403 सदस्यों के मध्य से दीर्घ अनुभव, संसदीय प्रक्रिया आदि के विशिष्ट ज्ञान एवं सदन में विशिष्ट योगदान तथा समितियों एवं सदन की अन्य गतिविधियों में योगदान आदि के आधार पर उत्कृष्ट विधायक का चयन किया जाना था।

महाना ने कहा कि सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्तमंत्री, सुरेश कुमार खन्ना को उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार हेतु चुना गया है। सुरेश कुमार खन्ना लगातार नौ बार से शाहजहांपुर से निर्वाचित हैं। वह सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। खन्ना का संसदीय ज्ञान एवं उनका सदन में योगदान उल्लेखनीय रहा है। वह विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल दल के नेता रहे हैं एवं वह विभिन्न समितियों के प्रमुख रहे हैं। समिति द्वारा चयनित किए गए उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार के रूप में एक विशिष्ट समारोह का आयोजन सदन में प्रस्तावित है।■

बाल श्रमिक विद्या योजना

कामकाजी बच्चों को आर्थिक मदद और शिक्षा

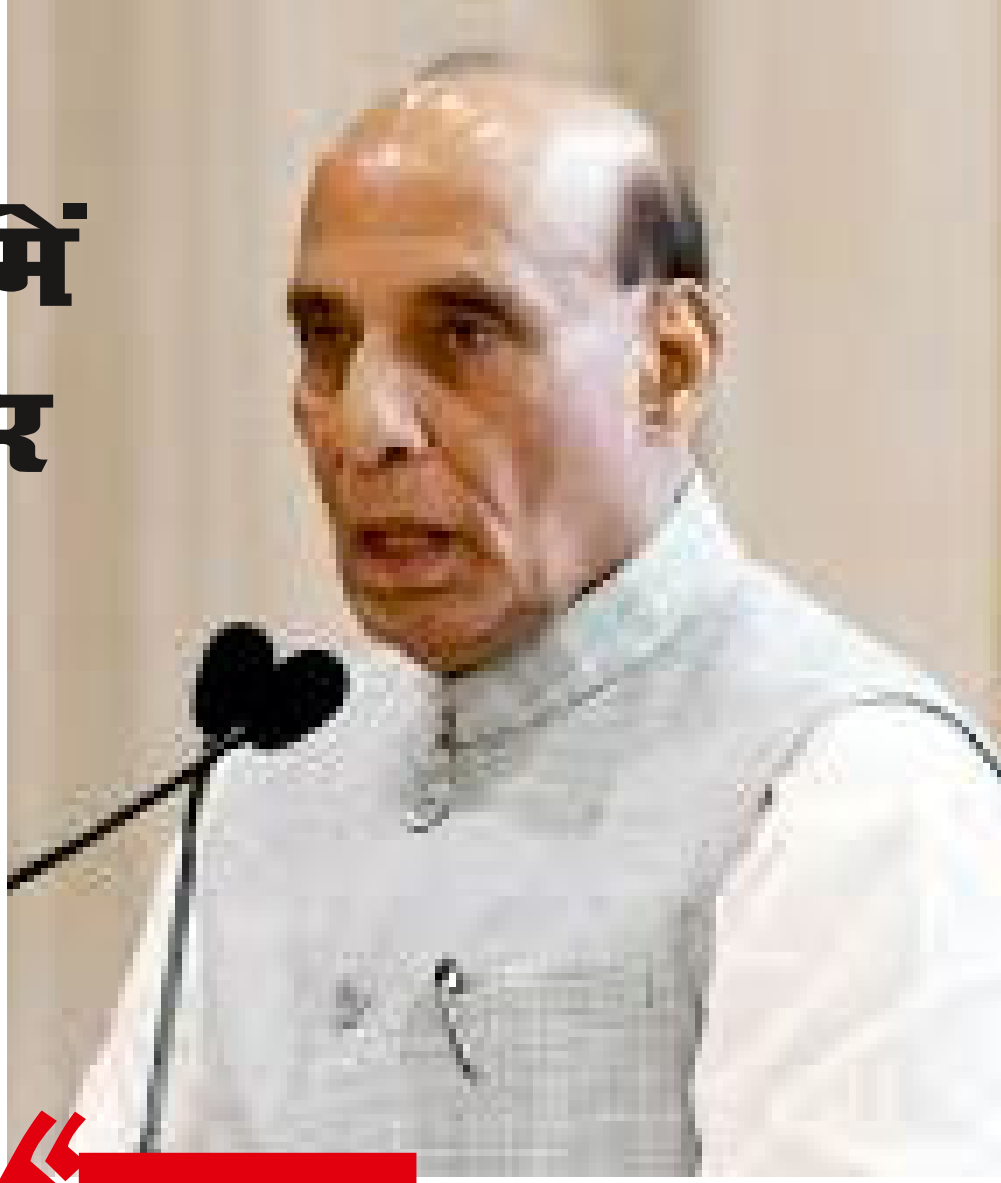


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन, शिक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा में शनिवार, 23 मई को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जिलों में लागू करने को कहा। अभी यह योजना 20 जिलों में चल रही है। योजना में 08 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों से जोड़कर आर्थिक मदद दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को और प्रभावी बनाने को कहा। सरकारी विभागों में भी इसके उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार मिलेगा। पोर्टल पर अभी 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। सभी औद्योगिक शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित होंगे। इन्हें केवल जुटान स्थल नहीं, बल्कि श्रमिक सहायता केंद्र बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था भी होगी। कानपुर में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास बनेगा। यहां बढ़ई, बिजली मिस्त्री, नलसाज जैसे कामों का प्रशिक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025–26 में 3,030 रोजगार मेलों से 3.74 लाख युवाओं को रोजगार मिला।'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' से 27,555 युवाओं का चयन हुआ, जिनमें 2,300 विदेश के लिए चुने गए। जर्मनी, जापान में रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण शुरू होगा। उन्होंने रोजगार संगम पोर्टल में कृत्रिम बुद्धि आधारित रोजगार मिलान और ऑनलाइन परामर्श व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब तक 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं।■

हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा यूपी



रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार, 30 मई को लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करते हुए उत्तर प्रदेश के बदले हुए स्वरूप को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पहचान कानून–व्यवस्था की चुनौतियों और माफिया तंत्र से जुड़ गई थी, लेकिन आज प्रदेश विकास, निवेश और सुशासन का नया मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश की छवि बदलने में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को व्यंग्य में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' के रूप में देखा जाता था। निवेशक यहां आने से हिचकिचाते थे और कानून–व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदली है। आज उत्तर प्रदेश 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का नया केंद्र बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दृढ़ता के साथ कानून–व्यवस्था को संभाला और अपराध व माफिया तंत्र पर प्रभावी कार्रवाई की, उससे प्रदेश में निवेश और विकास का नया वातावरण तैयार हुआ है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका को केवल एक पर्यटन स्थल या पार्क मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय चेतना, सैन्य परंपरा और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहां प्रदर्शित युद्धपोत, हथियार और नौसैनिक उपकरण वास्तविक हैं, जो भारतीय सेनाओं के शौर्य और समर्पण की कहानी बताते हैं।

उन्होंने कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यबोध के लिए प्रेरित करेगा। रक्षामंत्री ने रिकॉर्ड समय में इस परियोजना को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका की स्थापना केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रदेश के इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गोमती नदी के नाम पर भारतीय नौसेना का प्रतिष्ठित युद्धपोत 'आईएनएस गोमती' वर्षों तक राष्ट्रसेवा करता रहा है।

इसी तरह लखनऊ की ऐतिहासिक पहचान और गोमती नदी का रिश्ता भी इस परियोजना को विशेष महत्व प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह वाटिका प्रदेश और भारतीय नौसेना के बीच भावनात्मक और ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक बनेगी। राजनाथ सिंह ने लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ यहां आएं और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को समझें। उन्होंने कहा कि नौसैनिकों की वर्दी केवल कपड़े का एक परिधान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और कर्तव्य का प्रतीक होती है। यह वाटिका युवाओं को उसी भावना से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दृढ़ता के साथ कानून–व्यवस्था को संभाला और अपराध व माफिया तंत्र पर प्रभावी कार्रवाई की, उससे प्रदेश में निवेश और विकास का नया वातावरण तैयार हुआ है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका को केवल एक पर्यटन स्थल या पार्क मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय चेतना, सैन्य परंपरा और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहां प्रदर्शित युद्धपोत, हथियार और नौसैनिक उपकरण वास्तविक हैं, जो भारतीय सेनाओं के शौर्य और समर्पण की कहानी बताते हैं।

अहिंसा परमो धर्मः ...सख्त रवैया भी जरूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार, 30 मई को कहा कि जब हम सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूत होंगे तो दुनिया भी मैत्री करेगी। कमजोर के आगे कोई नहीं झुकता। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, इसलिए पूरी बात कहना सीखें। भारत की ऋषि परंपरा प्रेरणा देती है कि "अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च" यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन सामने वाला देश व समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अंततः हिंसा ही अपनानी पड़ेगी। देश के दुश्मन के साथ यही हमारा धर्म है और भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ यह करती है। मुख्यमंत्री शनिवार, 30 मई को राजधानी में 19 करोड़ रुपये की लागत से 02 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका (नौसेना शौर्य संग्रहालय के द्वितीय चरण) के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित सैन्य अधिकारियों, कार्मिकों व जन–समूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ इस वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नौसेना बैंड की अनुपम प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सोच बड़ी होती है और व्यक्ति बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है तो सकारात्मक परिणाम आता है, जो युवाओं को नई प्रेरणा प्रदान करता है। इस वाटिका में आने वालों को भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे सैनिक किन सम–विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, यह भी जानने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी युवाओं के जीवन में चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा होगी। नौसेना का लक्ष्य उसकी विराट सोच का प्रतीक है। सीएम ने आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" का जिक्र किया और कहा कि आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए बड़ी सोच भी चाहिए। संकुचित सोच या भाव से बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की संकल्पना को रखा है। उन्होंने हर भारतवासी को पंचप्रण के साथ जुड़ने के लिए कहा है। हमारे मन में सेना व यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हो। जब भारतीय सैनिक माइनस डिग्री टेंपरेचर, रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी



सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन-कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया व अपराधियों ने जीना हराम कर दिया था। असुरक्षित वातावरण में विकास व निवेश की संभावनाएं क्षीण हो गई थीं। लेकिन, जब हमारे सैनिक सुरक्षा के प्रति प्रतिब)ता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें।

और समुद्र की लहरों का मुकाबला करते हुए सीमाओं की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चौन की नींद सोते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन-कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया व अपराधियों ने जीना हराम कर दिया था। असुरक्षित वातावरण में विकास व निवेश की संभावनाएं क्षीण हो गई थीं। लेकिन, जब हमारे सैनिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणास्थल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री व रक्षामंत्री ने 25 दिसंबर को किया था तो दूसरी तरफ नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम का अद्भुत केंद्र यहां प्राप्त हुआ है। अभी इसका विस्तार भी होगा।

सीएम ने कहा कि रक्षामंत्री जी कह रहे थे कि प्रदेश में भारतीय सेना से जुड़े अन्य कार्यों के लिए तत्काल प्रस्ताव दिए जाएं। मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण चौराहों पर भारतीय सेना के वे टैंक रखे जाने चाहिए, जो अब वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं। इन्हें जो भी देखेगा, उसके मन में भारतीय सेना में जाने और सेना के प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा। उसे राष्ट्रभक्ति की नई प्रेरणा प्राप्त होगी, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता।

सीएम ने रक्षामंत्री की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सुव्यवस्थित ढंग से समय सीमा के अंदर कार्य पूरा कराने के लिए नौसेना अध्यक्ष व उनकी टीम के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपरा, विरासत, सुरक्षा से जुड़े इस नौसेना वाटिका केंद्र का भ्रमण कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। यह केंद्र प्रदेश के युवाओं को नई सोच के साथ देखने, सुनने व जानने का अवसर प्रदान कर रहा है। आईएनएस गोमती ने लंबे समय तक भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सीमा की रक्षा की। 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर स्थापित किया गया।

इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा व ब्रजलाल, पर्यटन/संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक योगेश शुक्ल, राजेश्वर सिंह, ओपी श्रीवास्तव, अमरेश कुमार, जय देवी, विधान परिषद सदस्य अवनीश सिंह, मुकेश शर्मा, पवन सिंह चौहान, उमेश द्विवेदी, लालजी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे।■

लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज

12 प्रस्ताव मंजूर

बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार, 18 मई, 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा।

बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है।

इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के बाद नए मेट्रो रूट लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का आज ऐलान किया गया है। नए और पुराने लखनऊ को जोड़ते हुए चारबाग स्टेशन से मेट्रो पुराने लखनऊ के बाजारों से होते हुए वसंत कुंज पहुंचेगी। मिर्जापुर में 765/400 केवी उपकेंद्र निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड के मल्टी स्पेशिएलिटी इंमरजेंसी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को भी हरी झंडी मिली। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर किया गया। आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी।

पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी कैबिनेट के ये फैसले साफ दिखाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फोकस है। योगी सरकार के फैसलों से चुनाव और विकास दोनों साधने की तैयारी है।■

गुप्त मतदान मतपत्र के जरिए हो चुनाव

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर देश में मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग उठाई और ब्रिटेन में हाल में हुए चुनावों का हवाला देते हुए शनिवार, 09 मई को कहा कि भारत में भी मतपत्र से मतदान होना चाहिए। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा, 'कल एक विकसित देश में चुनाव हुए। इंग्लैंड और ब्रिटेन में गुप्त मतदान मतपत्र के जरिए हुआ। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश मतपत्र से चुनाव करा सकते हैं, तो भारत में भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह समाजवादियों की पुरानी मांग है।'

उन्हें ईवीएम से ही फिर हराएंगे और सत्ता से हटाएंगेः उन्होंने कहा, 'आपने (भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए) हमें सिर्फ ईवीएम से हराया है। लेकिन हम उन्हें ईवीएम से ही फिर हराएंगे और सत्ता से हटाएंगे।' अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन में स्थानीय परिषदों तथा स्कॉटलैंड और वेल्स की संसदों के चुनावों में मतगणना जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने शुक्रवार को स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी स्वीकार की थी।

संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वानः यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान भी किया। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'हम सभी को बहुस्तरीय चुनाव माफिया से लड़ना होगा। लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और द्रमुक नेता एम के स्टालिन के साथ अपनी तस्वीर साझा किए जाने तथा सपा–कांग्रेस गठबंधन टूटने की अटकलों पर यादव ने कहा, 'यह भाजपा की फैलायी नकारात्मकता है।'



पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही बीजेपीः भाजपा केवल विभाजन और संघर्ष की राजनीति करती है। सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, 'भाजपा जितना पैसा चुनाव में खर्च कर सकती है, उतना कोई दल नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जनता बदलाव लाएगी।' उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की संभावित तैनाती पर उन्होंने कहा, ष्उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय बल आएंगे, वे उत्तर–पूर्व और दक्षिण भारत से होंगे। बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां भेजे गए थे। पहली बार केंद्रीय बलों को चुनाव के बाद 15 दिन की छुट्टी दी गई है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के गठन के समय उसके भीतर इस बात पर बहस थी कि वह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर चलेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'भाजपा के गठन के समय पारित प्रस्तावों में समाजवादी विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में पार्टी सांप्रदायिक और पूंजीवादी साबित हुई। खुद को समाजवादी दिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मंच पर जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाई।' तेल कंपनियों के घाटे का जिक्र करते हुए यादव ने कहा, ष्सरकारी तेल कंपनियों के घाटे का बोझ आखिरकार जनता पर डाला जाएगा। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। सरकार नहीं, बल्कि आम लोग इसकी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि मुनाफाखोरी कम नहीं होने दी जा रही है। ■

लड़ाई चुनाव प्रक्रिया की नहीं देश को बचाने की है

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल दौरे के बाद शुक्रवार, 08 मई को कहा कि चुनावी महाधांधली और महाबेईमानी देखकर लगा कि अब लड़ाई केवल चुनाव प्रक्रिया बचाने की नहीं, बल्कि देश को बचाने की है।

सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार यादव ने कहा कि आज देश उन हाथों में है जो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, स्वतंत्रता, समता, न्याय, गरिमा, एकता–अखंडता, सद्भाव, बंधुत्व, महिलाओं के मान–सम्मान तथा युवाओं, किसानों, मजदूरों, शोषित, वंचित और गरीब, यानी पीडीए के हक और अधिकारों के घोर विरोधी हैं।

यादव ने कहा– ये लोग किसके एजेंट हैं? स्वदेशी की बात कर विदेश से पैसा लेने वाले ये लोग कौन हैं? ये संगठन गैर पंजीकृत क्यों हैं और भूमिगत क्यों रहते हैं? कोविड के नाम पर जमा चंदे का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने पूछा– योजना आयोग खत्म कर देश का विकास क्यों रोका गया? शिक्षा पर कब्जा कर देश की मानसिक शक्ति खोखली क्यों की जा रही है? सरकारी स्कूल बंद कर आम जनता के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र क्यों रचा गया?

उन्होंने कहा कि विश्वगुरु का दावा करने वाले, विदेश भागे देश के लुटेरों को वापस क्यों नहीं ला रहे? उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिकता फैलाकर एकता तोड़ने और राजनीतिक दलों को तोड़कर राज–व्यवस्था नेस्तनाबूद करने पर वे क्यों आमादा हैं? यादव ने कहा अब निर्णायक समय आ गया है। हम सबको मिलकर इन देश विरोधी नकारात्मक ताकतों को हमेशा के लिए हराना होगा, देश को बचाना होगा ■

भोजशाला वाग्देवी का मंदिर



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने लंबे समय से चल रहे भोजशाला प्रकरण में शुक्रवार, 15 मई अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एएसआई इसके प्रशासन और प्रबंधन पर निर्णय ले सकते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में एक और अहम मांग की गई थी। क्या वो यह कि राजा भोज की आराध्या मानी जाने वाली वाग्देवी सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम से वापस भारत लाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस पर कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं और सरकार इस विषय पर विचार सकती है।

मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का विवाद लंबे समय से चल रहा था। यहां पर बार–बार यह कहा जा रहा था कि यह कमाल मौला की मस्जिद है। हिंदू पक्ष बार–बार कह रहा था कि यह मंदिर है। लेकिन अब इस बीच यह जो लंबे समय से विवाद चल रहा था, इसको लेकर हाईकोर्ट ने 15 मई को एक फैसला लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भोजशाला मंदिर है। यह कोई मस्जिद नहीं है। विदित हो कि 2003 से यहां पर एक अनुमति दी गई थी कि यहां पर आकर के नमाज पढ़ी जा सकती लेकिन अब पूरी तरीके से यहां पर हिंदुओं को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि यहां पर पूरी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं और इसे मां सरस्वती का मंदिर माना है। लंबे समय से हिंदू पक्ष इस बात को लेकर लड़ रहा था। एएसआई ने लंबा सर्वेक्षण किया। 98 दिनों तक यहां पर सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद यह फैसला आया है। 2003 का एएसआई का वो आदेश भी कोर्ट ने रद कर दिया है जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की इजाजत दी गई थी। अब नमाज पर रोक लग गई है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। एएसई को जगह की देखभाल और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। मुस्लिम समुदाय के लिए कोर्ट ने यह कहा है कि अगर वह धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन मांगे तो राज्य सरकार इस पर विचार करें। हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में एक और अहम मांग की गई थी। क्या वो यह कि राजा भोज की आराध्या मानी जाने वाली वाग देवी सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम से वापस भारत लाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस पर कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं और सरकार इस विषय पर विचार सकती है।

फैसले की चार बड़ी बातें...

1. धार्मिक चरित्र मंदिरः एएसआई सर्वे, स्थापत्य विश्लेषण, शिलालेखों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने परिसर का धार्मिक चरित्र सरस्वती मंदिर और धार्मिक चरित्र तय करने में इन्हें अहम साक्ष्य माना।

2. एएसआई रिपोर्ट अहमः रिपोर्ट में 94 मूर्तियां, 150 संस्कृत–प्राकृत शिलालेख और मंदिर शैली के स्तंभों का जिक्र है। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया था, जबकि एएसआई ने कहा, विशेषज्ञों की मदद से सर्वे हुआ, मुस्लिम भी शामिल थे।



भोजशाला का इतिहास 11वी शताब्दी से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि यहां मां सरस्वती का मंदिर और विद्या केंद्र था। दावा है कि 12वीं–13वीं शताब्दी में मंदिर को ध्वस्त कर वहां मकबरा और मस्जिद का निर्माण किया गया। 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। यह परिसर 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम के तहत भी संरक्षित है।

3. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट: मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, संरक्षित स्मारक इस कानून से बाहर हैं। भोजशाला 1904 से संरक्षित स्मारक है।

4. जैन पक्ष का दावा: जैन पक्ष ने परिसर को जैन मंदिर, गुरुकुल बताया था। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड और पुरातात्विक सामग्री इसे जैन मंदिर घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं।

हिंदू पक्ष ने दी थी कई दलील: सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला को मंदिर बताते हुए कई ऐतिहासिक सबूत पेश किए गए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि यहा लंबे समय से वसंत पंचमी सहित अन्य अवसरों पर पूजा–अर्चना की परंपरा रही है।

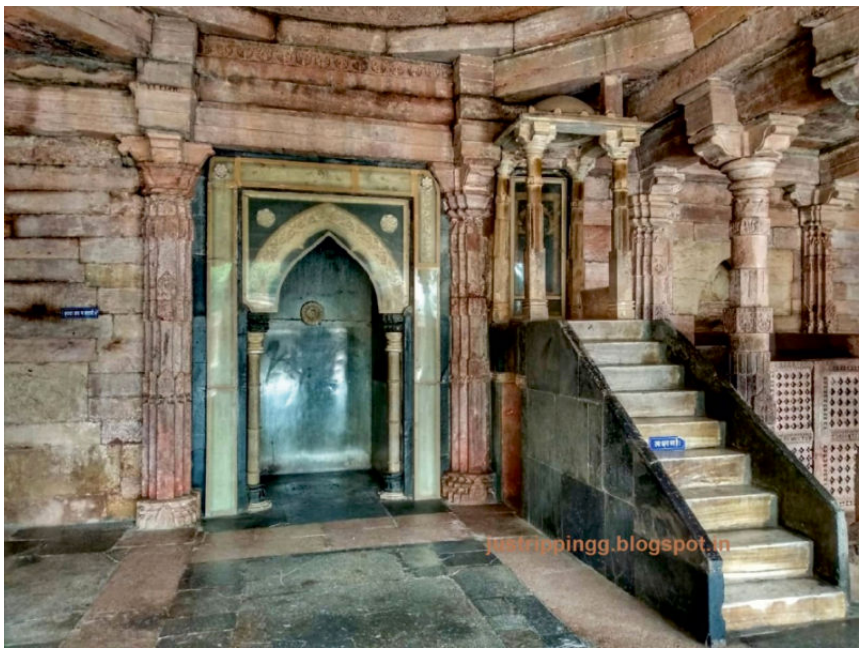
मुस्लिम पक्ष ने उठाए थे सवाल: कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम समुदाय ने पक्षपातपूर्ण बताया। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावो को मजबूत करने के मकदस से तैयार की गई है। एएसआई ने अदालत में कहा कि सर्वे पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से किया गया है।

क्या है भोजशाला का इतिहास: भोजशाला का इतिहास 11वी शताब्दी से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि यहां मां सरस्वती का मंदिर और विद्या केंद्र था। दावा है कि 12वीं–13वीं शताब्दी में मंदिर को ध्वस्त कर वहां मकबरा और मस्जिद का निर्माण किया गया। 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। यह परिसर 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम के तहत भी संरक्षित है। लंबे समय से यह विवाद बना हुआ था कि इस धर्म इस इस स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है? हिंदू पक्ष इसे देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र बताता रहा है। जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। कहा जाता है कि यहां पर 1000 से 1055 ईसवी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के बड़े भक्त कहे की ऐसा मान्यता है। उन्होंने यहां 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की जिस जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गौशाला को ध्वस्त कराया था। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और उसके बाद 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहां पर 98 दिनों तक सर्वे भी करवाया था। परिसर से चांदी, तांबे, एलुमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के 10वीं 11वीं शदी के इंडो सेशियन काल 13वीं 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत और 15वीं 16वीं शतादी के मालवा सुल्तान और मुगल काल के समय के हैं। कुछ खिड़कियों और खंभों पर देवी देवताओं या पशुओं की आकृतियां उकेरी हुई पाई गई। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े और वास्तु शिल्प देखे गए। खंभों की कुछ बीमों पर चार सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इनमें गणेश, ब्रह्मा, नर्सिंग आदि उनकी तस्वीरें शामिल हैं।

कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहां पर 98 दिनों तक सर्वे भी करवाया था। परिसर से चांदी, तांबे, एलुमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के 10वीं 11वीं शदी के इंडो सेशियन काल 13वीं 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत और 15वीं 16वीं शतादी के मालवा सुल्तान और मुगल काल के समय के हैं। कुछ खिड़कियों और खंभों पर देवी देवताओं या पशुओं की आकृतियां उकेरी हुई पाई गई। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े और वास्तु शिल्प देखे गए।

भोजशाला : गोमूत्र से शुद्धिकरण, गर्भगृह में अखंड ज्योत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई की नई गाइडलाइन के बाद रविवार, 17 मई को धार स्थित भोजशाला परिसर में ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। वर्षों के इंतजार के बाद हिंदू समाज को अब साल के 365 दिन बिना किसी रोक-टोक के पूजा-अर्चना की अनुमति मिलने पर श्र)ालुओं में भारी उत्साह नजर आया। वहां पहली बार हिंदू समाज ने खुले तौर पर पूजा-अर्चना की और जश्न मनाया। श्र)ालु मां वाग्देवी का चित्र लेकर परिसर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और हनुमान चालीसा के बीच पूजा हुई। सुबह से ही भोजशाला परिसर में भक्ति, उल्लास और जश्न का माहौल बना रहा।



हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने भी नया आदेश जारी किया है. अब साल के सभी दिन बिना किसी रोक–टोक के हिंदुओं का प्रवेश होगा. एएसआई ने नई प्रेस रिलीज में 'कमाल मौला मस्जिद' का उल्लेख हटाकर केवल 'भोजशाला' नाम दर्ज कर लिया. पहले कानूनी दस्तावेजों में परिसर को भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद लिखा जाता था. आदेश में भोजशाला को 'राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला' के रूप में संबोधित किया गया है. हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई के आदेश के बाद हिंदू संगठनों व श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई की नई गाइडलाइन के बाद रविवार, 17 मई को धार स्थित भोजशाला परिसर में ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। वर्षों के इंतजार के बाद हिंदू समाज को अब साल के 365 दिन बिना किसी रोक–टोक के पूजा–अर्चना की अनुमति मिलने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। वहां पहली बार हिंदू समाज ने खुले तौर पर पूजा–अर्चना की और जश्न मनाया। श्रद्धालु मां वाग्देवी का चित्र लेकर परिसर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और हनुमान चालीसा के बीच पूजा हुई। सुबह से ही भोजशाला परिसर में भक्ति, उल्लास और जश्न का माहौल बना रहा।

रविवार सुबह सूर्योदय होते ही हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोजशाला पहुंचे। समिति के नेतृत्व में श्रद्धालु मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का भव्य तैल चित्र लेकर परिसर में पहुंचे। भोजशाला में प्रवेश करते ही सनातन परंपरा के अनुसार पूरे परिसर को गो–मूत्र छिड़ककर शुद्ध किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच विधि–विधान से पूजा–अर्चना शुरू हुई।

रंगोलियों से सजा गर्भगृह, स्थापित की गई अखंड ज्योतः इस खास अवसर पर भोजशाला के गर्भगृह को रंग–बिरंगी और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया था। वहीं परिसर के बाहर स्थित ज्योति मंदिर की 'अखंड ज्योत' को पूरे सम्मान के साथ गर्भगृह के भीतर स्थापित किया गया। मां वाग्देवी के चित्र की स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा परिसर "जय श्रीराम" और "मां वाग्देवी की जय" के जयकारों से गूंज उठा। खुशी के इस माहौल में महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी प्रसन्नता जाहिर की।

प्रशासन रहा अलर्टः पूरे धार्मिक आयोजन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। राजीव रंजन मीणा और सचिन शर्मा सुबह से ही मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून–व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वे खुद भी पूजा–अर्चना में शामिल हुए और मां वाग्देवी की आराधना की। भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने कहा कि नई गाइडलाइन मिलने के बाद अब भोजशाला को एक नए और भव्य स्वरूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। वर्षों के इंतजार के बाद मिले इस अधिकार को श्रद्धालु बड़ी सांस्कृतिक जीत के रूप में देख रहे हैं। ■

बदलाव की ओर बंगाल

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सुवेंदु अधिकारी सरकार ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2023 के पंचायत चुनावों के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इन मामलों को पिछली सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित और बंद मामलों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में मारे गए तीन सौ इक्कीस भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार



यदि चाहें तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के लंबे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

इसके अलावा, नई सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करने और पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की खुली छूट देने की घोषणा की है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी की राजनीतिक पहचान को महत्व न दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।

साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में अवैध पशु बाजारों को बंद करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस परगना जिलों में चल रहे अवैध पशु बाजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को पैंतालीस दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन में हो रहे बदलावों पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी पशु के वध से पहले उसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नई सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ ही राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहे सिंडिकेट राज और अवैध खनन पर भी सरकार ने कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर सक्रिय कथित सिंडिकेट नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछली व्यवस्था में निर्माण सामग्री और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण था, जिसे खत्म करना आवश्यक है।

सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और गैर वैधानिक संस्थाओं में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी

बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर सख्ती, वंदे मातरम् को अनिवार्य करना, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

नई सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते तेजी से पूरा करने को कहा है।

साथ ही राज्य की नई भाजपा सरकार ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के छहों पद गाने होंगे। सरकार का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को जन गण मन के समान दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इसके अलावा, कानूनी ढांचे में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू करने की घोषणा भी की गई है। यह नया आपराधिक कानून पुराने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कार्यान्वयन लंबित था। नई सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकारी नौकरियों के इच्छुक युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा चालीस से बढ़ाकर पैंतालीस वर्ष कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से अवसरों से वंचित युवाओं को लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

जनगणना प्रक्रिया को भी नई सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब बिना किसी राजनीतिक अहंकार के केंद्र के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी।

इसके अलावा, प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर के मानकों से जोड़ना है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के आठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसे पश्चिम बंगाल की नौकरशाही में बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है।

बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर सख्ती, वंदे मातरम् को अनिवार्य करना, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाती रही है और अब सरकार बनने के बाद उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि राज्य की एक बड़ी आबादी भी लंबे समय से ऐसे बदलावों की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला। नई सरकार के शुरुआती फैसलों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक दिशा दोनों में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ■

योगी की राह चले शुभेंदु

शुभेंदु अधिकारी बतौर सीएम काम बंगाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है. इसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि ममता बनर्जी के शासन में ऐसे–ऐसे नियम–कानून राज्य की जनता पर थोप दिए गए थे, जिससे नाखुशी–नापसंदगी के बावजूद कोई विरोध में बोल नहीं पाता था. सत्ता बदलने के साथ ही शुभेंदु ने ममता के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है. शुभेंदु के फैसलों में पूर्ववर्ती सरकार की तुष्टीकरण नीतियां भी हैं, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिलता था.

उत्तर प्रदेश के सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ नाथ ने अपनी पहली प्राथमिकता अपराधियों की नकेल कसने की तय की थी. इसके लिए उन्होंने 04 स्टेप्स तय किए. पहला यह कि बड़े से बड़े सूरमाओं को उनके रसूख के कारण कोई राहत–रियायत नहीं मिले. दूसरा, इन्हें जेल की सीखचों तक पहुंचाने के लिए धर–पकड़ के साथ बुलडोजर की संस्कृति भी उन्होंने शुरू की. तीसरा काम योगी ने यह किया कि एनकाउंटर की रफ्तार बढ़ाई. कई अपराधी मारे गए तो कुछ जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे. अपराधियों में इस कदर भय समाया कि उन्हें पेशी के लिए जेल से अदालत जाने में भी एनकाउंटर का खतरा महसूस होने लगा।

गोवंश वध पर बंदिशः मुसलमानों में बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी की परंपरा है. बड़े पैमाने पर गोवंश का वध होता है. आजादी के बाद इस पर अंकुश का कानून तो बना, लेकिन चुनावी लाभ के लिए बंगाल की किसी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई. बंगाल के रास्ते बड़े पैमाने पर गोवंश की तस्करी होती रही है. ममता राज में यह संस्थागत रूप ले चुका था. पशु तस्करी मामले की जांच सीबीआई भी पहले से कर रही है. शुभेंदु ने पुराने कानून को ही झाड़–फूंक कर बाहर निकाला और लागू कर दिया है. गोवंश का वध अब सख्ती से बंगाल में अपराध माना जाएगा. कुर्बानी भी खुले में नहीं होगी. इसे लेकर मुसलमानों में नाराजगी तो है, लेकिन अब उनका मन भी बदलने लगा है. यूपी में भी बकरीद के दौरान गोवंश वध पर बंदिश सख्ती से लागू है।

लाउडस्पीकरों पर कसी नकेलः शुभेंदु अधिकारी ने भी योगी आदित्नाथ की तरह



धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर बंदिश लगा दी है. इतना ही नहीं, सड़कों पर नमाज के लिए भी शुभेंदु ने योगी की तरह रोक लगाई है. योगी तो इस मामले में पहले से ही स्पष्ट रहे हैं. वे साफ कहते हैं कि आबादी कंट्रोल करो या शिफ्ट में नमाज पढ़ो. सड़क पर इसकी छूट कत्तई नहीं. शुभेंदु भी इसी अंदाज में दिख रहे हैं बंगाल में पहले इसके खिलाफ मुसलमानों ने जबरदस्त आवाज उठाई, लेकिन आखिरकार वे बेमन से ही सही, इसके लिए तैयार हो गए हैं. मुसलमानों को केंद्र कर योगी के और भी कई फैसले हैं, जिन्हें शुभेंदु सरकार ने लागू किया है या इसकी तैयारी में हैं।

घुसपैठियों के खिलाफ एक्शनः शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ के हाथों सौंपने का पुलिस और आरपीएफ को बंगाल सरकार ने निर्देश दिया है. शुभेंदु कहते हैं कि जेल में रख कर करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे. सीधे उनके देश वापस भेजा जाएगा. बुलडोजर और एनकाउंटर का सिलसिला तो यूपी–बिहार की तरह सरकार बदलते ही बंगाल में शुरू हो गया है. बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं, यह बात तो ममता बनर्जी भी कभी कहती थीं. लेकिन, अब तो उनके सुर ही बदल गए हैं. वे नहीं मानतीं कि बंगाल में कोई घुसपैठिया है।

मुसलमानों का मिल रहा साथः सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही, गायों की कुर्बानी पर रोक, बकरीद की छुट्टी में कटौती जैसे शुभेंदु अधिकारी के फैसलों से शुरू में मुसलमानों की नाराजगी तो रही, लेकिन आहिस्ता–आहिस्ता अब उनका मन बदलने लगा है. हालांकि उनसे अधिक ममता बनर्जी को शुभेंदु के फैसलों पर आपत्ति है. अब तो उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है. गायों की बलि के संबंध में कोलकाता की ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद के इमाम की अपील से साफ हो गया है कि बंगाल के मुसलमान टकराव के मूड में नहीं हैं. वे सरकार के फैसले को कबूल करते हैं. हालांकि आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमांयू कबीर जैसे कुछ लोग हो सकते हैं, जिन्हें सरकार का यह फैसला स्वीकार नहीं है।

योगी–शुभेंदु एक राह के राहीः शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ को कड़े फैसले लेने में इसलिए आसानी है कि दोनों बहुमत वाली सरकार चला रहे हैं. दोनों के काम–धाम एक जैसे दिख रहे हैं. यूपी के मुसलमान भाजपा से भले नफरत करें, लेकिन योगी के वे ज्यादा करीब होते दिख रहे हैं. अतीक अंसारी और आजम खां जैसे कई बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ योगी सरकार ने सख्ती की. मुसलमानों का मुखर विरोध नहीं दिखा. इसकी वजह योगी शासन की सख्ती तो रही है, लेकिन बड़ा कारण यह रहा है कि योगी सरकार ने अपराध के मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं किया. सिर्फ मुसलमान अपराधियों का ही एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि राजपूत–ब्राह्मण जाति के अपराधी भी एनकाउंटर में मारे गए. बंगाल की शुभेंदु सरकार और योगी के एक जैसे फैसलों और एक्शन में समानता से दोनों के बीच एक अघोषित–अचर्चित बांडिंग दिख रही है. इसका फायदा 2027 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिल सकता है. इनके फैसलों में हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण का संदेश साफ दिख रहा है. भाजपा की ताकत भी यही रही है। ■

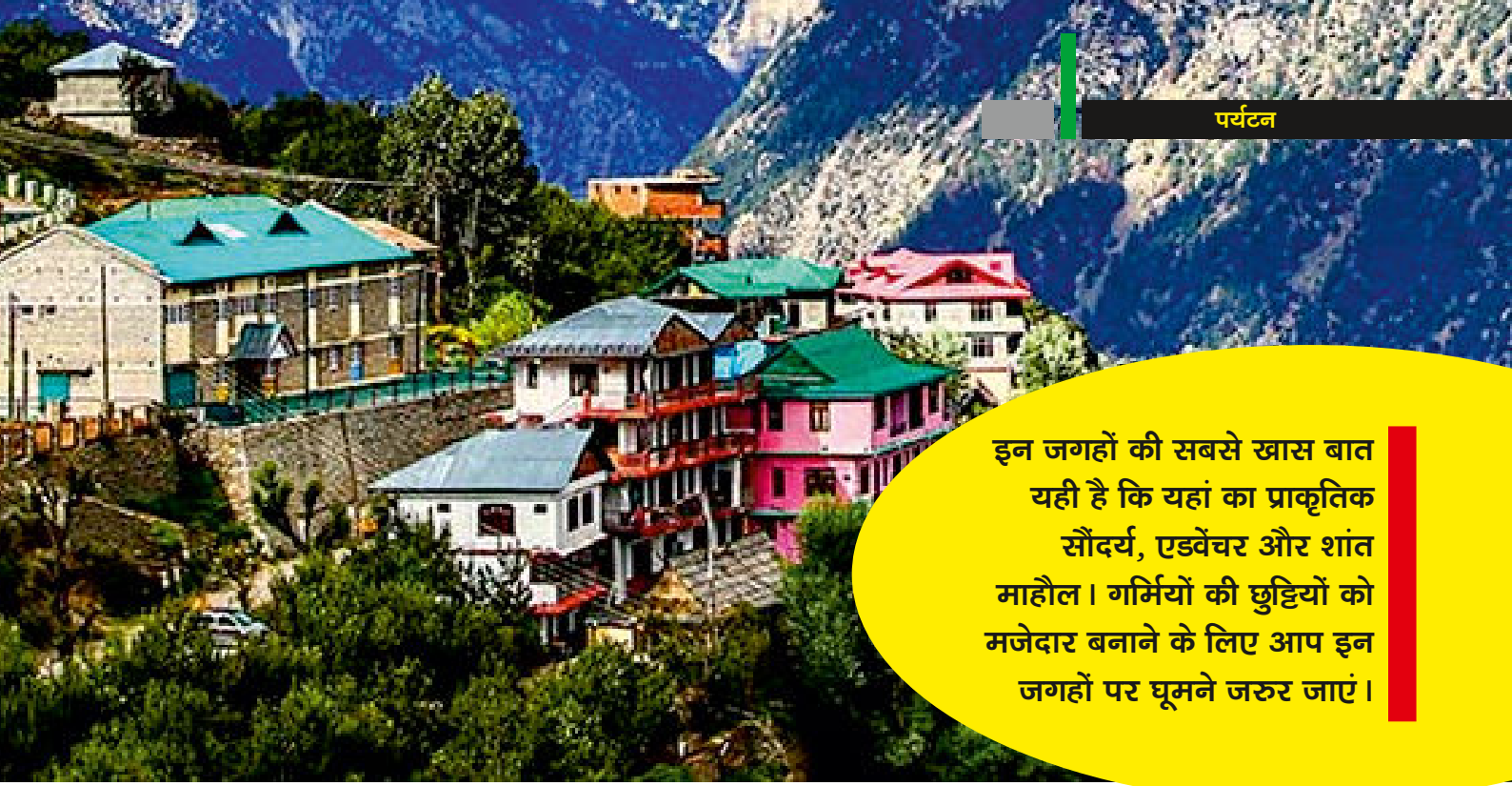
घुसपैठिए अब सीधे बीएसएफ के हवाले

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार, 21 मई को कहा कि हिरासत में लिए गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। खबरों के अनुसार, यह निर्देश 20 मई से लागू हो गया है और इसकी सूचना राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दोनों को दे दी गई है। बंगाल की नई भाजपा सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था के तहत, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ की सीमा चौकियों पर ले जाया जाएगा।

भारत में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां चिलचिलाती गर्मियों के दौरान भी बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल जाती है। रोहतांग पास, लद्दाख, गुलमर्ग, युमथांग घाटी और औली जैसे स्थान मई-जून में भी अपनी ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके नजारों के लिए मशहूर रहते हैं।

तपती गर्मी के बीच बर्फ का आनंद

उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए औली सबसे शानदार जगह है। आपको बता दें कि, उत्तराखंड का औली स्कीइंग के लिए मशहूर है, लेकिन गर्मियों में भी यहां की ठंडी वादियां और आसपास की बर्फ पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। यहां से नंदा देवी पर्वत का नजारा बेहद शानदार नजर आता है।



इन जगहों की सबसे खास बात यही है कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर और शांत माहौल। गर्मियों की छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए आप इन जगहों पर घूमने जरुर जाएं।

हिमाचल प्रदेश का रोहतांग के नजदीक गर्मियों में बर्फ देखने को मिलती है। मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह मई और जून में बर्फ से ढकी रहती है। पर्यटक यहां पर स्नो स्कूटर, स्कीइंग और बर्फ में खेलने का मजा ले सकते हैं। यहां शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। रास्ते में नजर आने वाले पहाड़ और झरने सफर को और भी खास बना देते हैं।

भारत में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां चिलचिलाती गर्मियों के दौरान भी बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल जाती है। रोहतांग पास, लद्दाख, गुलमर्ग, युमथांग घाटी और औली जैसे स्थान मई–जून में भी अपनी ठंडी हवाओं और बर्फीले नजारों के लिए मशहूर रहते हैं। इन खूबसूरत जगहों पर लोग गर्मी से राहत पाने, स्नो एक्टिविटीज का मजा लेने और प्राकृतिक वादियों की सैर करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इन जगहों की सबसे खास बात यही है कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर और शांत माहौल। गर्मियों की छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए आप इन जगहों पर घूमने जरुर जाएं।

रोहतांग पासः हिमाचल प्रदेश का रोहतांग के नजदीक गर्मियों में बर्फ देखने को मिलती है। मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह मई और जून में बर्फ से ढकी रहती है। पर्यटक यहां पर स्नो स्कूटर, स्कीइंग और बर्फ में खेलने का मजा ले सकते हैं। यहां शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। रास्ते में नजर आने वाले पहाड़ और झरने सफर को और भी खास बना देते हैं।

लद्दाखः लद्दाख किसी जन्नत से कम नहीं है। मई–जून की छुट्टियों में घूमने के लिए लद्दाख सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, यहां पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी। खासतौर पर खारदुंग ला और चांग ला जैसे पास पर सफेद बर्फ की मोटी परत आपके वेकेशन को शानदार बना देंगी। यहां पर आप बाइक ट्रिप भी कर सकते हैं।

गुलमर्गः कश्मीर का गुलमर्ग को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर बर्फीले नजारे और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए यहां जरुर घूमने जाएं। ऊंची चोटियों पर बर्फ देखने को मिलती है। गुलमर्ग गोंडला राइड से बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा बेहद ही शानदार लगता है। गर्मियों के दौरान यहां पर मौसम काफी ठंडा बना रहता है।

युमथांग घाटीः बर्फ के सुंदर नजारे और फूलों की चादर से ढकी यह जगह आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सिक्किम की युमथांग वैली को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। मई–जून के दौरान यहां पर बर्फील पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, रंग–बिरंगे फूल और ठंडी हवाएं एकदम सुकून दिलाएंगी। नेचर लवर के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

औलीः उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए औली सबसे शानदार जगह है। आपको बता दें कि, उत्तराखंड का औली स्कीइंग के लिए मशहूर है, लेकिन गर्मियों में भी यहां की ठंडी वादियां और आसपास की बर्फ पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। यहां से नंदा देवी पर्वत का नजारा बेहद शानदार नजर आता है।■



कॉकरोच जनता पार्टी
क्या सिर्फ एक छलावा मात्र है?

संतोष कुमार पाठक

15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जिस शब्दावली और तेवरों के साथ बेरोजगार युवाओं को कश्वकरोच के साथ जोड़ा, उससे देश में एक नया ही तूफान खड़ा हो गया। हालांकि अगले ही दिन जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी पर सफाई भी दे दी।



सत्य कभी–कभी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विचित्र होता है। आज से पहले शायद ही कभी किसी ने ऐसा सोचा भी होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जब लोगों में अपने आपको कॉकरोच कहने की होड़ लग जाएगी। देश भर में 'मैं भी कॉकरोच' जैसा एक बड़ा अभियान शुरू हो जाएगा। लोग, खासतौर से लाखों युवा 'मैं भी कॉकरोच' जैसे मीम्स और बैनरों के जरिए न केवल अपने आपको कॉकरोच कहने में गर्व महसूस करेंगे बल्कि हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाने की भी कोशिश करेंगे।लेकिन ऐसा हुआ और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी सोचने–समझने का मौका तक नहीं मिला।

15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जिस शब्दावली और तेवरों के साथ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच के साथ जोड़ा, उससे देश में एक नया ही तूफान खड़ा हो गया। हालांकि अगले ही दिन जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी पर सफाई भी दे दी। लेकिन उसके बाद भी विरोध के स्वर बंद नहीं हुए।

देशभर में सरकारी सिस्टम से नाराज लाखों युवा अलग–अलग अंदाज में लगातार अपना गुस्सा तो जाहिर कर ही रहे थे लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 11,500 किमी दूर बैठे एक भारतीय युवा अभिजीत दीपके (जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं) के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत 'कॉकरोच जनता पार्टी' बना दी। इसके बाद देखते ही देखते भारत के लोकतंत्र में कुछ ऐसा होता हुआ नजर आया , जो इससे पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा।

देखते–देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फॉलोअर्स की संख्या 02 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने वाली है। यह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की कुल संख्या 93 लाख से लगभग ढाई गुणा ज्यादा है।

इस बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी लगातार चर्चा में रहे। पार्टी के एक्स अकाउंट पर कभी रोक लगाई गई तो कभी वेबसाइट को डाउन करने का आरोप लगाया गया। जैसे ही लोगों ने इस पार्टी के इतिहास–भूगोल को खंगालना शुरू किया, सकते में आए अभिजीत दीपके ने तुरंत सफाई शुरू कर दी। इस बीच उन्होंने पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज को हैक करने का दावा भी किया और जब यह ठीक हुआ तो विवाद पैदा करने वाले पार्टी के संस्थापक मेघनन्द को उनकी ही पार्टी फॉलो करना बंद कर चुकी थी।

मतलब कहीं न कहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो फिलहाल सामने से नजर नहीं आ रहा है लेकिन जिसका आभास तो हो ही रहा है। बीजेपी इस पार्टी को विदेशी धरती से चलने वाले विपक्षी दल का टूलकिट बता रही है तो वहीं कई वरिष्ठ पत्रकार और बौद्धिक जमात के लोग इसे बीजेपी की बी टीम के रूप में पेश कर रहे हैं। अभिजीत दीपके की भी कई हरकतें, संदेह पैदा कर रही है। अभिजीत द्वारा एक खास पार्टी के समर्थक माने जाने वाले पत्रकारों को ही इंटरव्यू देना, विवादित व्यक्ति को अनफॉलो कर पहले कुछ खास पत्रकारों को फॉलो करना और फिर उन्हें भी अनफॉलो कर देना। सोचिए जो व्यक्ति

शुरुआत से ही इतना ज्यादा सेलेक्टिव हो, उसके पीछे कितनी बड़ी टीम या कितना बड़ा दिमाग काम कर रहा होगा जो भारत के लोकतांत्रिक आंदोलन के मिज़ाज, भारत की मेनस्ट्रीम और नई मीडिया (यूटूबर्स) की आदतों को कितनी अच्छी तरह से समझता है।

आंदोलन के जरिए, देश में एक माहौल पैदा करने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को महारत हासिल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है और जो वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन चलाना और इसे लोकप्रिय बनाने के तौर–तरीके भूल चुकी है। यह भी गौर करने वाली बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी को चंद बड़े पत्रकार अपने–अपने यूट्यूब चैनल पर जितना स्पेस दे रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्पेस मेनस्ट्रीम मीडिया दे रहा है। हाल के वर्षों में ऐसा कब हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए।

इस लेख के लेखक ने अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को बहुत ही शुरुआत से कवर किया था जिसकी सबसे खास बात यह थी कि प्रेस कांफ्रेंस के लिए आने वाले न्यौते में जिस केजरीवाल का नाम सबसे लास्ट में 'और अरविंद केजरीवाल' लिखा आता था, उस पार्टी में अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बचे रह गए हैं। याद कीजिएगा कि, उस दौर में भी अन्ना–अरविंद के आंदोलन पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को करप्ट व्यक्ति के तौर पर ही देखा जाने लगा था और आज भी अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं तो एक खास इको–सिस्टम के लोग (पत्रकार भी) तुरंत सामने आकर आपकी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए पूछने लगते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?

लेकिन ऐसा कहने वाले लोग पुरानी कहावत को भूल जाते हैं कि 'दूध का जला छाछ भी फूंक–फूंककर पीता है'। वैसे भी लोकतंत्र की पहली शर्त तो यही होती है, 'सवाल पूछने की आज़ादी' और सवालों से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। जो भी नेता या संगठन अपने आपको सवालों से ऊपर उठाने की कोशिश करता है,उसका एक ही संदेश निकलता है कि उसकी नियत साफ नहीं है।

लेकिन ऐसा कहने वाले लोग पुरानी कहावत को भूल जाते हैं कि 'दूध का जला छाछ भी फूंक–फूंककर पीता है'। वैसे भी लोकतंत्र की पहली शर्त तो यही होती है, 'सवाल पूछने की आज़ादी' और सवालों से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। जो भी नेता या संगठन अपने आपको सवालों से ऊपर उठाने की कोशिश करता है,उसका एक ही संदेश निकलता है कि उसकी नियत साफ नहीं है।

यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में खासकर युवाओं में बहुत गुस्सा है। लेकिन यह देश इससे पहले भी ऐसे अनुभवों से गुजर चुका है जब देश के युवाओं के गुस्से का इस्तेमाल कुछ खास लोगों ने अपने–अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए किया। ऐसे लोगों ने युवाओं को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए, ऐसे–ऐसे झूठे और लुभावने वादे किए जिन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं था। इसलिए इस बार भारत के लोगों खासकर युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है।

देश में बदलाव लाने का कोई भी अभियान देश की धरती से ही चलना चाहिए और किसी भी तरह के नए व्यक्ति या संगठन पर भरोसा करने से पहले लोगों को आंख बंद करके अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि उस नए संगठन, आंदोलन या व्यक्ति के अभियान से सबसे ज्यादा फायदा किस राजनीतिक दल अथवा नेता को होगा?– लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)





सनातन विरोध की राजनीति पर जनता का लोकतांत्रिक प्रहार



–प्रेम शुक्ल
(राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा)

सोचिए उस माली की मूर्खता को, जो उस वृक्ष की जड़ें काटने निकलता है, जिसकी छांव में वह स्वयं पला–बढ़ा हो। भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। एक तरफ वह सनातन, जो हजारों वर्षों की तपस्या, त्याग और ज्ञान की नींव पर खड़ा है, जो इस देश की सांसों में रचा–बसा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनेता, जिन्होंने वोट की भूख में अंधे होकर इसी सनातन को अपशब्द कहना, हिंदू आस्था को कोसना और भारत की आत्मा को ललकारना अपनी राजनीति का हथियार बना लिया। उन्हें लगा, हिंदू समाज बिखरा हुआ है, आस्था को रौंदते रहो, कोई प्रतिकार नहीं होगा। लेकिन यह देश गीता की भूमि है। यहां लिखा है–

'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम।

अर्थात, जब–जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब एक शक्ति जागती है। इस बार वह शक्ति किसी रणक्षेत्र में नहीं, मतपेटी में जागी और जनता ने वह जवाब दिया, जिसकी इन नेताओं ने कल्पना भी नहीं की थी।

सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु की राजनीति से सामने आया, जहां द्रमुक नेताओं ने खुले मंचों से सनातन धर्म को 'डेंगू और मलेरिया' जैसी बीमारी तक कह दिया। द्रमुक के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता ए. राजा ने इससे भी आगे बढ़कर सनातन की तुलना 'एच.आई.वी.' और 'कुष्ठ रोग' जैसी बीमारियों से कर दी। द्रमुक के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटाइन रवींद्रन ने सनातन धर्म को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की 'बुद्धि की कमी' का कारण बता दिया और अब इस सनातन–विरोधी राजनीति में एक नया और चिंताजनक अध्याय जुड़ गया है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टी.वी.के. ने हाल ही में सरकार बनाई लेकिन सत्ता की कुर्सी गर्म होने से पहले ही इस दल के नेताओं ने सनातन के विरुद्ध अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया।

टी.वी.के. के विधायक और तमिलनाडु मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष वी.एम. एस. मुस्तफा ने खुले मंच से घोषणा की, 'सनातन को समाप्त करने के लिए ही हम रणक्षेत्र में उतरे हैं।' जो पार्टी अभी–अभी जनता का विश्वास लेकर सत्ता में आई, उसके नेता पहले ही दिन से सनातन को मिटाने की भाषा बोलने लगें, यह तमिलनाडु की जनता के साथ विश्वासघात है और पूरे देश के लिए एक कड़ी चेतावनी। देश ने यह सब देखा और समझ लिया कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने की सुनियोजित मानसिकता है।

कम्युनिस्ट पार्टियों ने दशकों तक



नास्तिकता के नाम पर सनातन परंपराओं का वैचारिक विरोध किया। इनके नेताओं और समर्थक बुद्धिजीवियों ने हिंदू रीति–रिवाजों, मंदिर परंपराओं और आध्यात्मिक आस्थाओं को बार–बार पिछड़ेपन, असमानता और सामाजिक उत्पीडन् से जोडने् का प्रयास किया। बिहार में रामचरितमानस जैसे पूजनीय ग्रंथ पर आर.जे.डी. से जुड़े नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणियां की गईं। यह केवल एक पुस्तक पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना पर हमला था, जो भारत को जोड़ती है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं को लगा कि हिंदू समाज चुप रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता सब देखती है और समय आने पर जवाब भी देती है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों से जुड़े कई नेताओं ने भी समय–समय पर हिंदू प्रतीकों और धार्मिक नारों पर सवाल उठाए।

इस हिंदू–विरोधी नैरेटिव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भगवान राम को मात्र एक 'पौराणिक पात्र' बता दिया और करोड़ों हिंदुओं के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हुए राम मंदिर प्राण–प्रतिष्ठा समारोह को 'नाच–गाना' कहकर उसका भद्दा मजाक उड़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र 'महाकुंभ' में गंगा स्नान का उपहास उड़ाया और चुनावी रैलियों में भगवा वस्त्र धारण करने वाले संतों को राजनीति से बाहर निकलने की धमकी दी। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने भी सनातन को बीमारी बताया था। उत्तराखंड में कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि 'कोरोना' भगवान कृष्ण ने भेजा था। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी एन.सी.पी. नेता जितेंद्र आव्हाड ने रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव को 'दंगे भड़काने वाले' त्यौहार बताकर हिंदू पर्वों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।



सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु की राजनीति से सामने आया, जहां द्रमुक नेताओं ने खुले मंचों से सनातन धर्म को 'डेंगू और मलेरिया' जैसी बीमारी तक कह दिया। द्रमुक के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता ए. राजा ने इससे भी आगे बढ़कर सनातन की तुलना 'एच.आई.वी.' और 'कुष्ठ रोग' जैसी बीमारियों से कर दी। द्रमुक के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटाइन रवींद्रन ने सनातन धर्म को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की 'बुध्दि की कमी' का कारण बता दिया और अब इस सनातन–विरोधी राजनीति में एक नया और चिंताजनक अध्याय जुड़ गया है।

पश्चिम बंगाल में स्थिति और भी चिंताजनक रही। वहां रामभक्तों पर हमले हुए, धार्मिक जलूसों को रोका गया और हिंदू आस्था को बार–बार अपमानित करने की घटनाएं सामने आईं। टी.एम.सी. की सांसद महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक मंच से मां काली के स्वरूप को लेकर बेहद अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणियां कीं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने जैसी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंडिया गठबंधन के घटक दलों का यह दुरूस्साहस केरल तक भी पहुंचा, जहां कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग ने एक रैली में खुलेआम नारे लगाए कि 'हिंदुओं को मंदिरों में फांसी पर लटका दिया जाएगा और जिंदा जला दिया जाएगा।'

पिछले 10 वर्षों में देश ने एक बड़ा बदलाव देखा है। जनता अब केवल जाति, क्षेत्र और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह भी देखती है कि कौन उसकी आस्था और संस्कृति का सम्मान करता है और कौन अपमान। इसिलिए जिन दलों और नेताओं ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, उन्हें जनता ने लगातार लोकतांत्रिक रूप से सबक सिखाया और अपनी वोट की ताकत से सत्ता से बाहर कर दिया।–लेख में लेखक के अपने विचार हैं।■

शिक्षा नहीं, ब्रांड बिक रहे हैं: कोचिंग संस्कृति के चौराहे पर शिक्षा

– प्रियंका सौरभ

भारत में शिक्षा को सदियों से ज्ञान, संस्कार और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है। शिक्षक को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त रहा है क्योंकि वह केवल विषय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण भी करता है। किंतु पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने इस आदर्शवादी अवधारणा को काफी हद तक प्रभावित किया है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती संख्या, सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण और बेहतर करियर की दौड़ ने कोचिंग उद्योग को एक विशाल आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया है। आज देश के अनेक शहरों में कोचिंग संस्थान शिक्षा व्यवस्था के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं, जिसका प्रभाव विद्यालयों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और यहां तक कि नीतिनिर्माताओं तक पर दिखाई देता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार ने इस प्रवृत्ति को और अधिक तीव्र बना दिया है। अनेक शिक्षक और कोचिंग संचालक यूट्यूब, इंस्टाग्राम तथा अन्य माध्यमों के जरिए लाखों विद्यार्थियों तक पहुँच रहे हैं। यह अपने आप में बुरा नहीं है। तकनीक ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है और दूरदराज़ के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन से हटकर व्यक्तिगत ब्रांड निर्माण, प्रचार और व्यावसायिक विस्तार तक सीमित हो जाता है। हाल ही में एक चर्चित टीवी बहस में वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा एक यूट्यूबर शिक्षक पर किया गया तंज सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना। इस घटना को लेकर लोगों की राय अलग–अलग हो सकती है। कुछ लोग इसे पत्रकारिता की तीखी टिप्पणी मानते हैं तो कुछ इसे शिक्षकों के प्रति अनादर के रूप में देखते हैं। किंतु इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा किया हैकृक्या शिक्षा का क्षेत्र अब अत्यधिक प्रचार और व्यवसायीकरण की ओर बढ़ चुका है? क्या विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया



जा रहा है जिसमें कोचिंग को सफलता की अनिवार्य शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है?

वास्तविकता यह है कि आज अनेक अभिभावक यह मानने लगे हैं कि बिना कोचिंग के उनका बच्चा किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। यह धारणा धीरे–धीरे इतनी गहरी हो गई है कि विद्यालयी शिक्षा की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगा है। कई परिवार अपनी आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ डालकर बच्चों को महंगी कोचिंग में भेजते हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों विद्यार्थी कोचिंग हब माने जाने वाले शहरों की ओर पलायन करते हैं।

इस प्रक्रिया में परिवार की बचत, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन सभी प्रभावित होते हैं। यह स्थिति केवल विद्यार्थियों की मानसिकता का परिणाम नहीं है। इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था की कुछ वास्तविक चुनौतियाँ भी हैं। विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं के बीच अक्सर अंतर दिखाई देता है। कई प्रतियोगी परीक्षाएँ ऐसी हैं जिनमें विद्यालयी पाठ्यक्रम से बाहर के विषय, विशेष प्रकार की तार्किक क्षमता या परीक्षा–विशिष्ट रणनीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

परिणामस्वरूप विद्यार्थियों और अभिभावकों को लगता है कि केवल स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। इस धारणा का लाभ कोचिंग उद्योग उठाता है और स्वयं को सफलता की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करता है। हालाँकि यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी कोचिंग संस्थानों को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अनेक संस्थान और शिक्षक ईमानदारी से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को अवसर दिए हैं जिन्हें अन्यथा बेहतर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ऑनलाइन शिक्षा ने लाखों युवाओं तक कम लागत में अध्ययन सामग्री पहुँचाई

है। इसलिए पूरे कोचिंग क्षेत्र को नकारात्मक रूप में चित्रित करना उचित नहीं होगा।

समस्या उन प्रवृत्तियों से है जहाँ शिक्षा की जगह प्रचार, व्यक्तिपूजा और अवास्तविक दावे केंद्र में आ जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में कुछ शिक्षकों ने स्वयं को ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है। उनके वीडियो, पोस्ट और विज्ञापन लगातार विद्यार्थियों के सामने आते रहते हैं। सफलता की कहानियों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जबकि असफल विद्यार्थियों की संख्या पर चर्चा कम होती है। कई बार यह आभास दिया जाता है कि किसी विशेष शिक्षक या कोचिंग से जुड़ना ही सफलता की गारंटी है। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी परीक्षा में सफलता अनेक कारकों पर निर्भर करती हैकृविद्यार्थी की मेहनत, पारिवारिक सहयोग, मानसिक स्थिति, अध्ययन संसाधन और समय प्रबंधन उनमें प्रमुख हैं।

एक अन्य चिंताजनक पहलू शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिकेंद्रित संस्कृति का बढ़ना है। कुछ शिक्षक अपने विषय या संस्थान से अधिक स्वयं के प्रचार पर ध्यान देते दिखाई देते हैं। विशाल होर्डिंग, लगातार विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियानों और व्यक्तिगत छवि निर्माण पर खर्च होने वाले संसाधन यह प्रश्न उठाते हैं कि शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी है या शिक्षक का ब्रांड? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, न कि व्यक्तित्व का अंधानुकरण। हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम की कोचिंग संस्कृति की तुलना भी चर्चा का विषय बनती रही है।

यह धारणा अक्सर व्यक्त की जाती है कि हिंदी माध्यम में कुछ शिक्षक अत्यधिक प्रचार पर निर्भर रहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी माध्यम में संस्थान अपेक्षाकृत संस्थागत पहचान को महत्व देते हैं। यद्यपि यह विभाजन पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत ब्रांडिंग की प्रवृत्ति कुछ क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ता है, जो विषयवस्तु की गुणवत्ता से अधिक लोकप्रियता और फॉलोअर्स की संख्या से प्रभावित होने लगते हैं।

इस पूरे परिदृश्य में सरकार और शिक्षा नियामकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालयी शिक्षा इतनी मजबूत हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की बुनियादी तैयारी वहीं से संभव हो सके, तो कोचिंग पर अत्यधिक निर्भरता स्वतः कम हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यालयी शिक्षा को अधिक कौशल आधारित और व्यावहारिक बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं, किंतु इन सुधारों का प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देने में समय लगेगा।

यह उद्देश्य प्रचार, ब्रांडिंग और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की भीड़ में खो जाता है, तो इसका नुकसान केवल विद्यार्थियों को नहीं बल्कि पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। समय की आवश्यकता है कि शिक्षा को पुनः उसके मूल उद्देश्य से जोड़ा जाए। विद्यालयों को मजबूत बनाया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं और पाठ्यक्रम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, कोचिंग संस्थानों के लिए पारदर्शी मानक बनाए जाएँ और विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि सफलता का सबसे बड़ा आधार उनकी अपनी मेहनत, अनुशासन और सीखने की क्षमता है।



साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की संरचना, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली में भी ऐसी पारदर्शिता और संतुलन होना चाहिए कि विद्यालयी अध्ययन और परीक्षा की अपेक्षाओं के बीच अनावश्यक अंतर न रहे। अभिभावकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि कोचिंग सफलता का एक साधन हो सकती है, लेकिन सफलता की एकमात्र शर्त नहीं। किसी भी संस्थान या शिक्षक के दावों को बिना जांचे–परखे स्वीकार करना उचित नहीं है।

विज्ञापन और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उनकी रुचि, क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी शिक्षक, चाहे वह कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो, उनकी मेहनत का विकल्प नहीं बन सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज्ञान प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन हैं, लेकिन उनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

लोकप्रियता और गुणवत्ता हमेशा एक ही चीज़ नहीं होतीं। किसी शिक्षक या संस्थान का चयन उसके प्रचार के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी शैक्षणिक उपयोगिता, विषय विशेषज्ञता और विद्यार्थियों को मिलने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर होना चाहिए। अंततः प्रश्न किसी एक पत्रकार, एक यूट्यूबर शिक्षक या किसी विशेष संस्थान का नहीं है। वास्तविक मुद्दा शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण और उस मानसिकता का है जिसमें सफलता को एक उत्पाद की तरह बेचा जाने लगा है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सोचने, समझने और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का है।

यदि यह उद्देश्य प्रचार, ब्रांडिंग और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की भीड़ में खो जाता है, तो इसका नुकसान केवल विद्यार्थियों को नहीं बल्कि पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। समय की आवश्यकता है कि शिक्षा को पुनः उसके मूल उद्देश्य से जोड़ा जाए। विद्यालयों को मजबूत बनाया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं और पाठ्यक्रम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, कोचिंग संस्थानों के लिए पारदर्शी मानक बनाए जाएँ और विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि सफलता का सबसे बड़ा आधार उनकी अपनी मेहनत, अनुशासन और सीखने की क्षमता है। तभी शिक्षा वास्तव में राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकेगी, न कि केवल एक लाभकारी व्यापार।

(कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।) ■

सेहत के प्रति जागरुक रहने वाले प्रतीक यादव की आकस्मिक मौत

समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार, 13 मई को यहां निधन हो गया। वह लगभग 38 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को तबीयत खराब होने पर सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार प्रतीक को कुछ समय पहले बीमार होने पर यहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह कुछ दिनों में तबीयत ठीक होने पर घर लौट आए थे।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। सेहत के प्रति बेहद जागरुक रहने वाले प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहते थे। हालांकि प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो गई थीं और वर्तमान में वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इसी साल जनवरी में दोनों के तलाक की भी चर्चाएं काफी सरगर्म थीं, मगर कुछ समय बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने की खबरें आई थीं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसे 'बेहद हृदयविदारक' बताया और परिवार



के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन बेहद हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।'

उन्होंने प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में लखनऊ में व्यापार और फिटनेस से जुड़े काम शुरू किए। वह शहर के एक जाने–माने जिम 'द फिटनेस प्लैनेट' को चलाते थे और स्वास्थ्य तथा फिटनेस में अपनी रुचि के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं।

बाद में, 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गईं और 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रतीक और अपर्णा ने 2011 में इटावा जिले में अपने परिवार के पैतृक गांव सैफई में आयोजित एक भव्य समारोह में शादी की थी। इस साल की शुरुआत में, प्रतीक यादव ने सार्वजनिक रूप से अपर्णा यादव के साथ अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में बात की थी। अपने वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में, उन्होंने अपर्णा पर परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपर्णा का ध्यान केवल प्रसिद्धि और प्रभाव पर है, और दावा किया था कि वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।■

अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित

प्रतीक यादव की अस्थियों का शनिवार, 16 मई को हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे धार्मिक रीति–रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में विसर्जन किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव, पुत्रियां प्रथमा और पद्मजा, अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट तथा भाई अमन सिंह बिष्ट अस्थि कलश लेकर जॉलीग्रांट पहुंचे, जहां से परिवार हरिद्वार पहुंचा। वीआईपी घाट पर तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन पांडेय ने पूरे विधि–विधान के साथ पूजन और पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई।

इसके बाद परिवारजनों ने मां गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अस्थि विसर्जन के दौरान योगगुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने प्रतीक यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

तारामंडलः आसमान में दिखने वाले तारों का वैज्ञानिक महत्व



तारामंडल देखने में आसान लगते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की गहराई समझने में मदद करते हैं। कुछ तारे करीब लगते हैं और कुछ बहुत दूर। जब हम कल्पना से इनके बीच लाइनें जोड़ते हैं तो सुंदर आकृतियां बन जाती हैं। अब सवाल है कि वैज्ञानिक तारामंडलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तारामंडल सिर्फ सुंदर नजारे नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसिज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह हैं क्योंकि तारामंडल लंबे समय तक लगभग एक ही जगह पर रहते हैं, इन्हें आसमान में निशान या लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नासा और खगोलविद तारों, नीहारिकाओं और अन्य खगोलीय वस्तुओं के नाम उन्हीं तारामंडलों के आधार पर रखते हैं जिनमें वे स्थित होते हैं। उल्का शावर्स के नाम भी संबंधित तारामंडल से लिए जाते हैं।

जब लोग अंधेरी रात के आसमान में चमकते तारों को देखते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये तारामंडल क्या है और वैज्ञानिक इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? वैज्ञानिक बताते हैं कि तारों के ये पैटर्न वास्तव में क्या है और इसका महत्व क्या है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस प्लेस पोर्टल पर तारामंडल के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। तारामंडल तारों के समूह होते हैं, जो पृथ्वी से देखने पर किसी खास आकार या चित्र जैसे दिखाई देते हैं। ये तारे आपस में जुड़े नहीं होते, बल्कि बहुत अलग–अलग दूरी पर स्थित होते हैं। फिर भी, जब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं तो वे जानवरों, चीजों या इंसानों की आकृति बनाते नजर आते हैं। पुराने समय से ही मानव संस्कृतियों ने इन पैटर्न को नाम दिए। आज दुनिया भर में 88 तारामंडलों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इनके नाम अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग रहे हैं, लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान में इन्हें तय किया गया है। रात में दिखने वाले तारामंडल आपकी पृथ्वी पर स्थिति और साल के समय पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। इसलिए हर मौसम में रात का आसमान बदलता रहता है।

तारे हर रात थोड़ा पश्चिम की ओर खिसकते दिखाई देते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी अलग–अलग तारामंडल दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में सितंबर महीने की रात आसमान देखें तो आपको 'मीन' तारामंडल दिख सकता है, लेकिन 'कन्या' नहीं दिखेगा क्योंकि वह उस समय सूर्य की दूसरी तरफ होता है।

तारामंडल देखने में आसान लगते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की गहराई समझने में मदद करते हैं। कुछ तारे करीब लगते हैं और कुछ बहुत दूर। जब हम कल्पना से इनके बीच लाइनें जोड़ते हैं तो सुंदर आकृतियां बन जाती हैं।

अब सवाल है कि वैज्ञानिक तारामंडलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तारामंडल सिर्फ सुंदर नजारे नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसिज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह हैं क्योंकि तारामंडल लंबे समय तक लगभग एक ही जगह पर रहते हैं, इन्हें आसमान में निशान या लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नासा और खगोलविद तारों, नीहारिकाओं और अन्य खगोलीय वस्तुओं के नाम उन्हीं तारामंडलों के आधार पर रखते हैं जिनमें वे स्थित होते हैं। उल्का शावर्स के नाम भी संबंधित तारामंडल से लिए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, हर साल अक्टूबर में होने वाली 'ओरियोनिड्स' उल्का शावर्स 'ओरियन' तारामंडल की दिशा से आती दिखाई देती है। नेविगेशन में तारामंडलों की भूमिका बहुत पुरानी है। सदियों से नाविक समुद्र में दिशा पता करने के लिए तारों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसे 'सेलेस्टियल नेविगेशन' कहते हैं। आज भी नासा के अंतरिक्ष यात्री इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आधुनिक जीपीएस या अन्य सिस्टम काम न करें तो तारामंडल बैकअप के रूप में काम आ सकते हैं।

यही नहीं रोबोटिक अंतरिक्ष यान भी तारों के नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। ये यान अपने कंप्यूटर में तारों का पूरा नक्शा रखते हैं और कैमरे से खींची तस्वीरों की तुलना करके अपना रास्ता तय करते हैं। इस तरह पुरानी तकनीक आज भी आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोगी साबित हो रही है।■

किन्नरों को जबरन वसूली का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 04 मई एक किन्नर की याचिका पर 'नेग' (दक्षिणा या उपहार) के नाम पर जबरन वसूली को गैर–कानूनी करार दिया है। अदालत ने इस तरह की वसूली को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध बताया है। यह केस उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले के किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुना जा रहा था, जिसमें रेखा देवी ने अपनी जजमानी का इलाका निर्धारित करने की अदालत से मांग की थी। याचिकाकर्त्ता का कहना था कि इलाकों की भौगोलिक सीमा स्पष्ट न होने के कारण, प्रायः किन्नरों के अलग–अलग समूहों के बीच झड़पें व हिंसा तक होती है। पर अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए उक्त निर्णय सुनाया।

यह सही है कि घर में खुशी के मौके पर, जैसे पुत्र या पुत्री का जन्म, विवाह या नए घर में गृह–प्रवेश के अवसर पर किन्नर बधाई देने आते हैं और नाच–गा कर अपना नेग मांगते हैं। भारत में यह अनूठी प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है। इसकी जड़ें पौराणिक काल में हैं। सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से स्वीकृत कथा रामायण से जुड़ी है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से जाते हैं, तो वे लोगों (पुरुषों और स्त्रियों) को वापस लौट जाने को कहते हैं। किन्नर (जो न पुरुष हैं न स्त्री) इस आदेश से खुद को बंधा नहीं मानते और राम की प्रतीक्षा में वहीं रह जाते हैं। 14 वर्ष बाद राम लौटते हैं तो उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर राम उन्हें वरदान देते हैं कि शुभ अवसरों पर उनका आशीर्वाद विशेष रूप से फलीभूत होगा। इसी वरदान को बधाई की परंपरा का मूल माना जाता है। किन्नर समुदाय गाते–बजाते, तालियां बजाते हुए आशीर्वाद देते हैं और बदले में नेग लेते हैं। यह मान्यता है कि उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और सौभाग्य लाती है। यह कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस दोनों में मिलती है।

इसी तरह महाभारत में अर्जुन का बृहन्नला रूप (तीसरे लिंग वाला) और शिखंडी जैसे पात्र तीसरे लिंग की मान्यता दिखाते हैं। लगभग 400 ईसा पूर्व लिखे गए कामसूत्र में किन्नरों का स्पष्ट उल्लेख है। वेदों, पुराणों



और अन्य शास्त्रों में भी किन्नरों का जिक्र मिलता है। किन्नरों को गायन, नृत्य और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा माना जाता था। कई विद्वान और स्रोत इस समुदाय की उपस्थिति को 4000 वर्ष से अधिक पुरानी बताते हैं। मुगल काल में हिजड़ों की भूमिका और संगठित हुई। वे हरम की रखवाली, दरबारी सेवाएं और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। बधाई की परंपरा इस काल में अधिक प्रचलित और संरचित रूप में चली, जहां वे शुभ अवसरों पर नृत्य–गान करके आशीर्वाद देते और नेग प्राप्त करते थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में उनकी सांस्कृतिक–सामाजिक स्थिति मजबूत थी। अंग्रेजों ने 1871 के 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' के तहत किन्नरों को अपराधी घोषित कर दिया, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका और सम्मान प्रभावित हुआ। आजादी के बाद यह कानून समाप्त कर दिया गया। इस तरह बधाई–नेग की परंपरा उत्तर भारत, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में आज भी जीवित है। कुछ राज्यों में सरकार ने नेग की दरें तय करने की कोशिश भी की है, पर उसमें विशेष कामयाबी नहीं मिली।

इसी अस्पष्टता का लाभ उठा कर किन्नर समुदाय प्रायः अपने जजमानों से जबरन वसूली करता है। कभी–कभी तो वसूली का तरीका बहुत अभद्र होता है। जिसमें जजमान के परिवार के सामने निर्वस्त्र हो जाना, भद्दी गालियां देना, बद्दुआएं देना और डराना धमकाना। कभी–कभी यह सब नाटक इस सीमा तक हो जाता है कि भयभीत जजमान अपनी आर्थिक हैसियत से कई गुना ज्यादा दे कर पिंड छुड़ाता है। ऐसी वसूली को 'नेग' कतई नहीं कहा जा सकता। ये सरासर गुंडई और अवैध वसूली का तरीका है, जिस पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ही कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जब बाकायदा सम्पूर्ण पुरुष होते हुए भी मर्द, स्त्री का रूप धारण कर किन्नर होने का दावा करते हैं और इस वसूली में अपनी ताकत दिखाते हैं। हमारी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार किन्नरों का शुभ अवसरों पर आकर गाना बजाना और बधाई देना शुभ माना जाता है। समाज इनका खुशी से स्वागत करता है और ऐसे अवसरों पर अड़ोसी–पड़ोसी जुट कर इनके साथ हास–परिहास भी करते हैं। यह एक स्वस्थ परंपरा है। प्रायरू छोटे शहरों और कस्बों में किन्नरों के समूह कई पीढियों तक अपने जजमान परिवारों से जुड़े रहते हैं और उनकी सुख–समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं।

देखा जाए तो सभी किन्नर संपन्न नहीं होते। वे अभावों में पलते हैं। उनकी आर्थिक, शैक्षिक या स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का उचित इंतजाम नहीं होता। फिर भी वे पारस्परिक सहयोग से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे में किन्नरों को नाचने–गाने या भीख मांगने से हटा कर छोटे व्यवसायों या नौकरियों में लगाने की जिम्मेदारी, सरकार और समाज दोनों की है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। पर आपराधिक तरीके से जबरन वसूली करने वाले किन्नरों से परिवारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को तत्परता से निभानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इस समस्या को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है।–विनीत नारायण, लेख में लेखक के अपने विचार हैं। ■

सोशल मीडिया नीति लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई: एडीजी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों को राज्य पुलिस की सोशल मीडिया नीति का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार, 15 मई को जारी एक परिपत्र में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अभिताभ यश ने कहा कि आठ फरवरी, 2023 को पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'सोशल मीडिया नीति–2023' लागू की जा चुकी है।



परिपत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मी सोशल मीडिया मंचों पर आपत्तिजनक सामग्री और रील पोस्ट कर नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां न केवल सरकारी कार्यों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा और छवि पर भी प्रतिकूल असर डाल रही हैं। परिपत्र के अनुसार, सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाए। साथ ही, आपत्तिजनक पोस्ट की प्रतियां उनके यूआरएल सहित आधिकारिक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।■

मनरेगा की जगह अब वीबी जी राम जी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में इसे भारत की ग्रामीण विकास संरचना में एक 'ऐतिहासिक परिवर्तन' बताया है, जो 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना के अनुरूप है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम एक जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। अधिसूचना में आश्वासन दिया गया है कि मनरेगा से नए ढांचे की ओर परिवर्तन से श्रमिकों के लिए कोई व्यवधान नहीं होगा।



अधिसूचना में कहा गया है, 30 जून तक मनरेगा के तहत जारी कार्यों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें बिना किसी रुकावट के नए ढांचे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा ई–केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी होने तक वैध रहेंगे, और यह भी कहा गया है कि जॉब कार्ड के बिना श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण कराना जारी रख सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि लंबित ई–केवाईसी के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि वेतन भुगतान, शिकायत निवारण, आवंटन मानदंड और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित नियमों का मसौदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया जाएगा। वीबी–जी राम जी अधिनियम के ढांचे के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्त वर्ष में 125 दिन के गारंटीकृत मजदूरी के रोजगार के हकदार होंगे, जो मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी से अधिक है।

रोजगार निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न करने पर श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के पात्र बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 2026–27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है। राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।■

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामला

कुलकर्णी ने 'सीक्रेट क्लास' में लिखवाए प्रश्न-उत्तर

सीबीआई ने नीट–यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच जारी है, मामले का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर कुलकर्णी ने पुणे में स्पेशल क्लास चलाकर छात्रों को परीक्षा के सवाल और जवाब लिखवाए। अब तक कई शहरों से सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक विवाद के बाद नीट परीक्षा रद्द कर 21 जून को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट–यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने इस मामले के कथित 'किंगपिन' पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी पुणे में रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है और उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले छात्रों को गुप्त तरीके से पेपर के सवाल और जवाब बताए। करीब 22 लाख छात्रों ने इस साल नीट–यूजी परीक्षा दी थी। लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यह परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित होगी।

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बना खास ग्रुपः सीबीआई जांच में सामने आया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पीवी कुलकर्णी ने अपनी साथी आरोपी मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर कुछ छात्रों का एक खास ग्रुप तैयार किया। मनीषा वाघमारे को 14 मई को गिरफ्तार किया गया था।

घर पर 'स्पेशल कोचिंग क्लास' में लिखवाए नोट्सः आरोप है कि कुलकर्णी ने किसी डिजिटल कॉपी या प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने पुणे स्थित घर पर 'स्पेशल कोचिंग क्लास' चलाकर छात्रों को सवाल और उनके सही जवाब डिक्टेट किए। इन गुप्त क्लासों में छात्रों को सवाल, विकल्प और सही उत्तर हाथ से अपनी कॉपी में लिखवाए गए। बाद में सीबीआई को जो हस्तलिखित नोट्स मिले, वे नीट–यूजी 2026 के असली केमिस्ट्री पेपर से पूरी तरह मेल खाते पाए गए।

एक प्रतिष्ठित कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर थे पीवी कुलकर्णीः जांच एजेंसी के अनुसार



पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले हैं और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में केमिस्ट्री फैकल्टी रह चुके हैं। वह करीब चार साल पहले रिटायर हुए थे। सीबीआई का दावा है कि कुलकर्णी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा प्रक्रिया से भी संबंध था, जिसके कारण उन्हें गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच मिली। हालांकि एजेंसी ने अभी उनके सटीक रोल की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

सीबीआई ने कई राज्यों में की छापेमारीः इस मामले की जांच 12 मई को सीबीआई ने अपने हाथ में ली, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। सबसे पहले यह मामला 07 मई को राजस्थान में सामने आया था। इसके बाद सीबीआई ने कई राज्यों में छापेमारी की और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अहम दस्तावेज जब्त किए। इन सभी की फॉरेंसिक जांच चल रही है।

कई शहरों में छापेमारी के बाद कुल सात आरोपी गिरफ्तारः अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर समेत कई शहरों से सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में यह भी पता चला है कि बिचौलियों का एक नेटवर्क छात्रों से लाखों रुपये लेकर उन्हें इस 'स्पेशल क्लास' के जरिए लीक सामग्री उपलब्ध करा रहा था।

कई शहरों में छापेमारी के बाद कुल सात आरोपी गिरफ्तारः अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर समेत कई शहरों से सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में यह भी पता चला है कि बिचौलियों का एक नेटवर्क छात्रों से लाखों रुपये लेकर उन्हें इस 'स्पेशल क्लास' के जरिए लीक सामग्री उपलब्ध करा रहा था।

जांच के दायरे में लातूर की रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेसः इस मामले में लातूर की रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) भी जांच के दायरे में आ गई है। सीबीआई ने संस्थान के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर से पूछताछ की है। 28 सदस्यीय सीबीआई टीम ने उनके घर पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की। हालांकि एजेंसी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि कोचिंग संस्थान का इस पूरे नेटवर्क से कितना संबंध था।■

पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर को आरक्षण क्यों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न 'क्रीमी लेयर' को लगातार आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जब माता-पिता अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं और आर्थिक सशक्तीकरण हो चुका है, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि यह चक्र समाप्त हो सके।



सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न 'क्रीमी लेयर' को लगातार आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जब माता–पिता अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं और आर्थिक सशक्तीकरण हो चुका है, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि यह चक्र समाप्त हो सके।

उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लगातार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार, 22 मई को कहा कि शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ–साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता को आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को सही ठहराया गया था।

याचिकाकर्ता के माता–पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा, ''अगर माता–पिता दोनों ही आईएएस अधिकारी हैं, तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ–साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है।'' उसने कहा, ''तो फिर, अगर ऐसे बच्चों के लिए भी आरक्षण की मांग की जाती रही, तो हम इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।'' उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर छात्रों के माता–पिता अच्छी नौकरियों में हैं और उनकी आय भी अच्छी–खासी है, तो ऐसे बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए कई आदेशों में पहले से ही यह प्रावधान है कि ऐसे समृद्ध वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाए, लेकिन अब उन आदेशों को ही चुनौती दी जा रही है। पीठ ने कहा, ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के मामले में, सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है। इसलिए, इस मामले में किसी न किसी तरह का संतुलन होना चाहिए।''

अधिकारियों ने पाया कि माता–पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी संयुक्त आय निर्धारित क्रीमी लेयर की सीमा से अधिक थी। याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करने का आधार उसके माता–पिता की आय थी जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और कथित तौर पर उनकी संयुक्त आय 8,00,000 रुपये से अधिक थी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, जिसमें उसे कुरुबा समुदाय का बताया गया था, रद्द कर दिया गया।■

सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह होंगे 38 जज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार, 17 मई को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026' जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जायेगी। इस अध्यादेश से 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956' में संशोधन किया गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत पांच मई को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा।

इससे उच्चतम न्यायालय में में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़कर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) हो जाएगी। विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसका व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष बढ़ते लंबित मामलों और मुकदमों से निपटने के लिए एक बेहतर कदम बताया है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2025 को उच्चतम न्यायालय में 81,394 लंबित मामले थे। ■

यमुनोत्री शुद्धि, गंगोत्री कृपा, केदारनाथ पश्चाताप

बद्रीनाथ का संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से है

चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रध्दालु अपनी आस्था लेकर चारधाम की यात्रा करने पहुंच रहे हैं। पिछले छह महीने से बंद इन मंदिरों के खुलते ही हर हर महादेव और जय बाबा बद्रीनाथ के जयकारों की आवाजें सुनने को मिल रही है। ताजा रिपोर्टो के अनुसार, चारधाम के कपाट खुलते ही शुरुआती दिनों में लगभग 02 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा करने आ रहे श्रध्दालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है।






चार धाम यात्रा को भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, जो हर साल लाखों भक्तों को हिमालय में स्थित यमुना मंदिर, गंगोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आकर्षित करती है। इन मंदिरों की दिखाई देने वाली भव्यता के पीछे कहानियों की एक समृद्ध परंपरा छिपी है। ये कहानियां केवल पौराणिक कथाएं ही नहीं हैं, बल्कि उन लाखों लोगों की आस्था की नींव हैं जो शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में इस यात्रा पर निकलते हैं।

यमुना नदी और ऋषि असित की कहानी: परंपरा के अनुसार, यह यात्रा यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री से शुरू होती है। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, लेकिन इसका महत्व ऋषि असित की किंवदंती से गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार, ऋषि असित ने अपना पूरा जीवन नदी के किनारे ध्यान करते हुए बिताया। बुढ़ापे में अपनी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी, उन्होंने अटूट श्रद्धा के साथ अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे। उनकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर, कहा जाता है कि देवी यमुना ने उनकी आँखों की रोशनी वापस लौटा दी। कृतज्ञता स्वरूप, ऋषि ने इस क्षेत्र पर दैवीय आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की, जिससे यह मान्यता बनी कि यहां के पवित्र जल में असाधारण आध्यात्मिक शक्ति है। यह कहानी इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्ची भक्ति शारीरिक सीमाओं को पार कर सकती है और दैवीय कृपा को आमंत्रित कर सकती है।

गंगोत्री और राजा भागीरथ की कहानी: अगला पड़ाव, गंगोत्री, हिंदू परंपरा की सबसे प्रतिष्ठित किंवदंतियों में से एक गंगा का पृथ्वी पर अवतरण से जुड़ा हुआ है। यह कहानी राजा भागीरथ के इर्द–गिर्द घूमती है, जिन्होंने अपने पूर्वजों को एक श्राप से मुक्त कराने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी प्रार्थनाएं तब स्वीकार हुईं जब भगवान शिव ने उस विशाल नदी को अपनी जटाओं में धारण करने की सहमति दी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि नदी का पृथ्वी पर अवतरण विनाशकारी नहीं होगा। माना जाता है कि नदी के पृथ्वी पर प्रवाहित होने से यह भूमि पवित्र हो गई और अनगिनत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह किंवदंती दृढ़ता और आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है, जिससे गंगोत्री आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक बन जाता है।

केदारनाथ और पांडवों की कहानी: चार धाम यात्रा के क्रम में केदारनाथ का एक विशेष स्थान है, जिसका मुख्य कारण महाभारत काल से इसका जुड़ाव है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, पांडवों ने युद्ध के दौरान हुई तबाही के लिए क्षमा मांगी और मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। हालांकि, भगवान शिव ने उनसे बचने का फैसला किया; उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और ज़मीन के अंदर समा गए। पांडवों ने उनका पीछा करते हुए केदारनाथ तक गए, जहाँ अंततः भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यह कथा पश्चाताप और दैवीय कृपा के विषयों को दर्शाती है। यह बताती है कि यद्यपि क्षमा का मार्ग कठिन हो सकता है, फिर भी सच्चा प्रयास और अटूट विश्वास मोक्ष की ओर ले जा सकता है।

बद्रीनाथ की कहानी: इस तीर्थयात्रा का अंतिम पड़ाव, बद्रीनाथ, भगवान विष्णु को समर्पित है और यह इस यात्रा की पूर्णता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गहन तपस्या की थी। उन्हें कठोर मौसम से बचाने के लिए, ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने एक 'बद्री' वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें आश्रय और सुख प्रदान किया था। यह कथा प्रकृति और दिव्यता के बीच के सामंजस्य का प्रतीक है, और आध्यात्मिक विकास में अनुशासन तथा तपस्या के महत्व को रेखांकित करती है। भक्तों के लिए, बद्रीनाथ केवल पूजा–अर्चना का स्थान ही नहीं, बल्कि परम मोक्ष और आंतरिक शांति का भी प्रतीक है। चार धाम यात्रा को अक्सर शरीर, मन और आत्मा की यात्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। इस यात्रा का प्रत्येक पड़ाव आध्यात्मिक विकास के एक भिन्न चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यमुनोत्री का संबंध शुद्धि से है, गंगोत्री का दैवीय कृपा से, केदारनाथ का पश्चाताप से, और बद्रीनाथ का आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से है।

सारी बीमारियों की जड़ गाढ़ा खून, कारण और घरेलू इलाज

शरीर में अगर खून गाढ़ा हो जाए तो कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है लेकिन ये होता क्या है और इसे ठीक करने का सही तरीका क्या है ये जानना भी जरूरी है। जब खून सामान्य से ज्यादा "चिपचिपा" या गाढ़ा हो जाता है, तो उसे मेडिकल भाषा में हाइपरकोएगुलेबल स्टेट या "थिक ब्लड" कहा जाता है। इसमें खून का बहाव धीमा हो सकता है और शरीर में थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है और थक्का जिस अंग में बनता है उस अंग से जुड़ी बड़ी समस्या शुरू हो जाती है जैसे दिमाग में थक्का जमने पर ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बन जाता है। यह कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई कारणों से बनने वाली स्थिति है। सही समय पर ध्यान न देने पर यह दिल, दिमाग और नसों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। आइए इसके कारण

गाढ़ा खून होने के मुख्य कारण:

1. शरीर में पानी की कमी : अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो यह समस्या आपको हो सकती है। कम पानी पीने से खून गाढ़ा होने लगता है क्योंकि शरीर में तरल मात्रा घट जाती है और खून चिपचिपा होने लगता है।

2. ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैटी डाइट: अत्यधिक तला–भुना, जंक फूड, घी–तेल और प्रोसेस्ड फूड खाने से खून में फैट बढ़ता है जिससे खून में अशुद्धियां बढ़ जाती है और खून थिक हो जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल लेवल से जोड़ कर देखा जाता है।

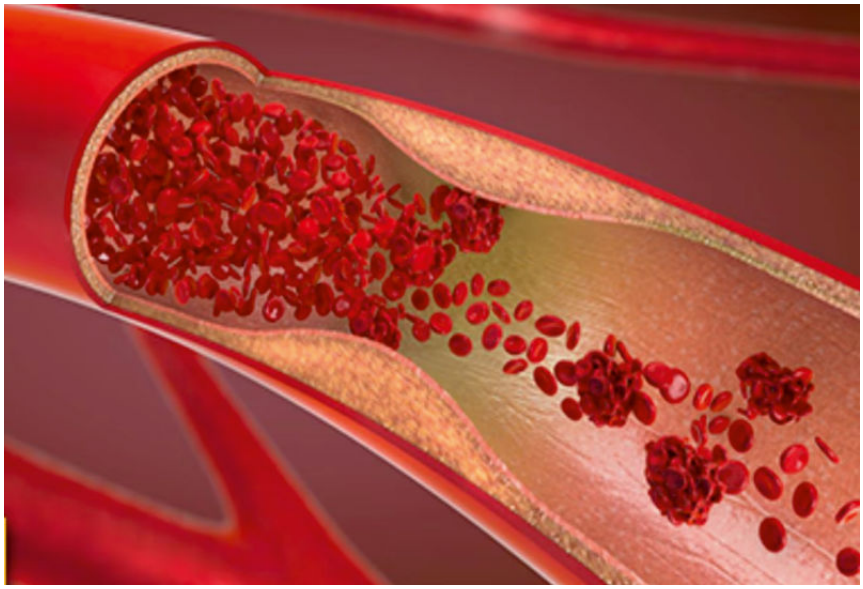
3. धूम्रपान और शराब: स्मोकिंग और एल्कोहल पीने वालों को भी ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये खून को गाढ़ा बनाकर नसों को नुकसान पहुंचाते हैं।

4. डायबिटीज: ब्लड शुगर बढ़ने से रक्तवाहिनियां प्रभावित होती हैं और खून की गुणवत्ता बदलती है। डायबिटीज मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत रहती है।

5. हाई ब्लड प्रेशर: जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत है उनका खून भी गाढ़ा हो सकता है क्योंकि उच्च रक्तचाप से रक्त प्रवाह प्रभावित होता है।

6. मोटापा: मोटापे में शरीर में सूजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे क्लॉट बनने का खतरा बढ़ता है।

7. लंबे समय तक बैठे रहना: एक ही जगह लंबे समय तक बैठने से सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ज्यादा सिटिंग जॉब करने वाले या फिर फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर



रखने वाले लोगों को ये दिक्कत रहती है।

8. ज्यादा आयरन या आरबीसी बनना: कुछ लोगों में शरीर जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स (आरबीसी) बनाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, अगर ये समस्या रहती है तो ब्लड टेस्ट जरूर करवाते रहे।

9. आनुवंशिक कारण: कुछ लोगों में क्लोटिंग की समस्या जन्मजात होती है। अगर आनुवांशिक कारण है तो इसका टेस्ट करवाते रहें।

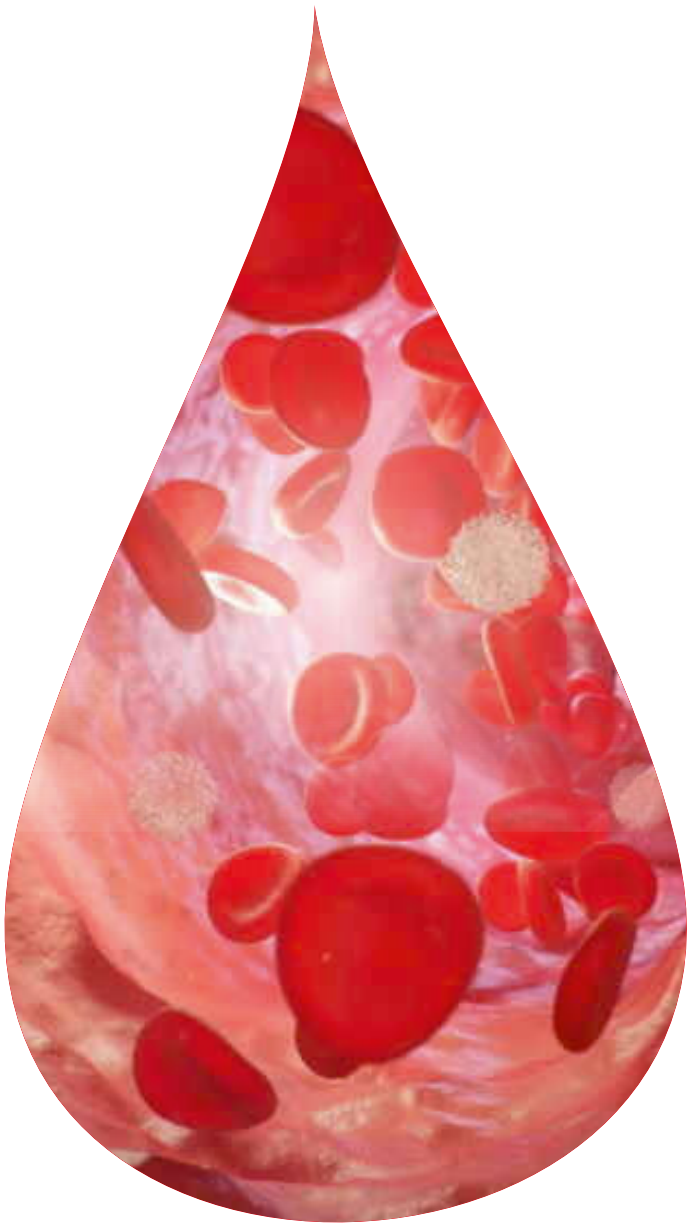
10. तनाव और खराब लाइफस्टाइल: नींद की कमी, तनाव और एक्सरसाइज न करना भी कारण बनते हैं।

लक्षण: बार–बार सिर दर्द, चक्कर आना, हाथ–पैर सुन्न होना, थकान, सांस फूलना, धुंधला दिखना, हाई बीपी, शरीर में भारीपन, पैरों में सूजन, सीने में दर्द। अगर बार–बार ये लक्षण हों, तो डॉक्टर से सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और कागुलेशन टेस्ट करवाना जरूरी है।

गाढ़ा खून होने से होने वाली हेल्थ प्राब्लम:

हार्ट अटैक: गाढ़ा खून दिल की नसों में क्लाउड (थक्का) बनाकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

स्ट्रोक: दिमाग की नस ब्लॉक होने पर स्टोक का खतरा बढ़ता है।



हार्ट अटैक का कारणः पैरों की नसों में थक्का जम सकता है।

फेफड़ों में क्लाउड, हाई बीपी और खराब सर्कुलेशनः यह जानलेवा स्थिति हो सकती है। हाई बीपी और खराब सर्कुलेशन से खून का प्रवाह धीमा होने लगता है।

किडनी और लीवर पर असरः खून की गुणवत्ता खराब होने से आर्गन प्रभावित होते हैं।

गाढ़ा खून होने पर कैसी डाइट खानी चाहिएः सबसे पहले नियम तो खाने से जुड़ा है। हल्का, प्राकृतिक और रक्त प्रवाह बढ़ाने वाला भोजन खाएं। खूब पानी पिएंः दिन में 2.5–3.5 लीटर पानी। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सूप बहुत फायदेमंद हैं।

खून पतला रखने वाले फलः बेहतरीन फल। अनार, संतरा, मौसंबी, अंगूर, कीवी, बेरीज, तरबूज आदि खाएं। इनमें एंटी आक्सीडेंट होते हैं जो खून सर्कुलेशन बेहतर करते हैं।

हरी सब्जियांः हरी सब्जियों में पालक, मेथी, ब्रोकोली, लौकी, टिंडा, करेला आदि का सेवन करें। फाइबर और मिनरल्स खून को स्वस्थ रखते हैं।

ओमेगा-3 वाले फूडः ये क्लॉट बनने का खतरा कम करने में मदद करते हैं। अलसी, अखरोट, चिया सीड्स, फैटी फिश खाएं।

लहसुन-अदरक और हल्दीः लहसुन, अदरक और हल्दी, ये प्राकृतिक ब्लड थिनर माने जाते हैं। हल्दी में कर्कूमिन होता है जो सूजन कम करता है।

फाइबर वाली चीजेंः ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, साबुत अनाज जैसे अनाज।

क्या नहीं खाना चाहिएः अगर आप खून पतला रखना चाहते हैं तो खाने में ज्यादा तला–भुना, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चीनी, अत्यधिक नमक, रेड मीट, ज्यादा घी–मक्खन जरूर करें। स्मोकिंग और एलकोहल से दूरी बनाकर रखें।

घरेलू नुस्खे भी आएंगे कामः

लहसुन का सेवनः सुबह खाली पेट 1–2 कली लहसुन गुनगुने पानी के साथ।

अदरक–नींबू पानीः सुबह हल्का गर्म पानी + नींबू + अदरक।

हल्दी वाला दूधः रात को हल्दी वाला दूध सूजन कम करता है।

अलसी पाउडरः 01 चम्मच अलसी रोज दही या पानी में।

दालचीनी और शहदः हल्की मात्रा में लेने से सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है।

आयुर्वेदिक उपायः आयुर्वेद में गाढ़े खून को अक्सर "रक्तदूषिता", खराब पाचन और बढ़े हुए कफ–पित्त से जोड़ा जाता है।

उपयोगी आयुर्वेदिक चीजेंः

अर्जुन छालः दिल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए उपयोगी मानी जाती है।

त्रिफलाः शरीर डिटाक्स• और डाइजेशन सुधारने में मदद करती है।

गुग्गुलः कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक माना जाता है।

आंवलाः विटामिन–सी और एंटी आक्सीडें से भरपूर।

तुलसीः रक्त संचार सुधारने में मददगार।

योग और लाइफस्टाइलः 30–45 मिनट वॉक,प्राणायाम, अनुलोम–विलोम, भ्रामरी, योगासन, वजन कंट्रोल रखें। मोटापा कम करना बहुत जरूरी है। 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद लें।

बहुत जरूरी बातेंः अगर आप पहले से ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं जैसे– वार्फेरिन या एस्प्रिन तो ज्यादा लहसुन, अदरक, हल्दी या आयुर्वेदिक ब्लड थीनिंग चीजें लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

तुरंत डॉक्टर को कब दिखाएंः गाढ़ा खून एक ऐसी स्थिति है जिसे सही डाइट, पर्याप्त पानी, नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

अगर ये लक्षण होंः अचानक सीने में दर्द। सांस लेने में दिक्कत। शरीर के एक हिस्से में कमजोरी। बोलने में दिक्कत। पैर में तेज सूजन या दर्द तो तुरंत मेडिकल सहायता लें।

तीन साल की उम्र में शुरू किया डांस, बनी सुपरस्टार

जब भी बॉलीवुड की सबसे शानदार डांसर और बेहतरीन अदाकाराओं का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले याद आती हैं माधुरी दीक्षित। अपनी खूबसूरत मुस्कान, एक्टिंग और शानदार डांसिंग स्टाइल से उन्होंने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। माधुरी के इस शानदार सफर की शुरुआत बेहद छोटी उम्र में हो गई थी।



माधुरी दीक्षित का डांस से रिश्ता तब जुड़ा, जब वह सिर्फ 03 साल की थीं। बचपन से ही उन्हें संगीत और नृत्य का बेहद शौक था। छोटी उम्र में ही उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया था और अपने हुनर से सभी को प्रभावित करने लगी थीं। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा कि मात्र 09 साल की उम्र में उन्हें कथक डांस के लिए स्कॉलरशिप मिली। यही वह समय था जब साफ हो गया था कि माधुरी आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर करेंगी।

15 मई, 1967 को मुंबई में जन्मीं माधुरी पढ़ाई में भी काफी अच्छी थीं। उनका सपना एक्ट्रेस बनने का नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई शुरू की थी और वह माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनका रुझान धीरे–धीरे फिल्मों की ओर बढ़ने लगा।

'अबोध' से की थी फिल्मी शुरुआतः माधुरी ने साल 1984 में बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन माधुरी की मासूमियत और एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वह बड़ी सफलता अभी भी उनसे दूर थी। बता दें की साल 1988 में रिलीज हुई तेजाब माधुरी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म के सुपरहिट गाने–एक दो तीन–– ने उन्हें रातों–रात स्टार बना दिया। 'मोहिनी' बनकर माधुरी ने जिस अंदाज में डांस किया, वह आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस गाने के बाद वह बॉलीवुड की नई सुपरस्टार बन गईं।

90 के दशक पर किया राजः इसके बाद माधुरी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दीं। दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन.! और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की सबसे बड़ी फीमेल स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग के साथ–साथ डांस का जादू भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उनके डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन्स को लोग आज भी कॉपी करते हैं।

साल 1999 में माधुरी ने डा0 श्री राम नेने से शादी की और अमेरिका शिफ्ट हो गईं। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि, फैंस का प्यार उन्हें दोबारा फिल्मों की दुनिया में वापस ले आया। उन्होंने आजा नच ले–– से शानदार वापसी की और देवदास में 'चंद्रमुखी' के किरदार से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। आज भी माधुरी दीक्षित की फिल्में, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी शोज के जरिए फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। वह कई रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती हैं।■



आईपीएल-2026
आरसीबी फिर चैंपियन



अहमदाबाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल–2026 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 155 रन बनाए। इसके जबाव में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर में पांच विकेट खोकर 161 रन बना कर जीत को अपनी झोली में डाल लिया।

खिताब जीतने के साथ ही आरसीबी को करोड़ों रुपये की प्राइज मनी भी मिली। फाइनल में हार के बावजूद गुजरात टाइटंस पर भी इनाम की बारिश हुई। वहीं प्लेऑफ में पहुंचने वाली अन्य दो टीमों को भी करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।

चैंपियन आरसीबी को मिले 20 करोड़ रुपये: आईपीएल–2026 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी प्रदान की गई।

रनरअप गुजरात टाइटंस को 13 करोड़: शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस फाइनल में हारकर उपविजेता रही। टीम को 13 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिली।

तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को भी मिला बड़ा इनाम: पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन का समापन तीसरे स्थान पर किया, जिसके लिए टीम को 07 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली। वहीं रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर रही। राजस्थान को 6.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन करते हुए कई व्यक्तिगत पुरस्कार अपने नाम किए और आईपीएल–2026 के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल रहे। वहीं आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर लीग में अपना दबदबा कायम रखा।■

खिलाड़ियों को मिले व्यक्तिगत अवॉर्ड और प्राइज मनी:

ऑरेंज कैप विजेता:
वैभव सूर्यवंशी: 10 लाख रुपये।

पर्पल कैप विजेता:
कगिसो रबाडा: 10 लाख रुपये।

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी):
वैभव सूर्यवंशी: 10 लाख रुपये।

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: वैभव सूर्यवंशी: 10 लाख रुपये।

सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवॉर्ड:
वैभव सूर्यवंशी: 10 लाख रुपये।

महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री कराएं स्टाम्प शुल्क में आकर्षक छूट पाएं



"महिलाओं को ₹10 लाख तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी जा रही थी। इसे बढ़ाकर अब ₹1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर लागू कर दिया गया है। आइए, माताओं, बहनों एवं बेटियों के पक्ष में रजिस्ट्री करवाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दें।"

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

स्टाम्प शुल्क में छूट

महिलाओं/बेटियों के पक्ष में निष्पादित होने वाले विलेखों (डीड्स) पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत

छूट की सीमा

महिलाओं/बेटियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों (डीड्स) पर स्टाम्प शुल्क में ₹1 करोड़ तक के मूल्य पर 1%

योजना का उद्देश्य

महिलाओं/बेटियों के संपत्ति पंजीकरण में वृद्धि करना है, जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें

छूट की सीमा में 10 गुना तक विस्तार

- ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ तक के विलेखों पर लाभ
- विलेख का मूल्यांकन ₹1 करोड़ से अधिक होने पर भी ₹1 लाख तक की छूट

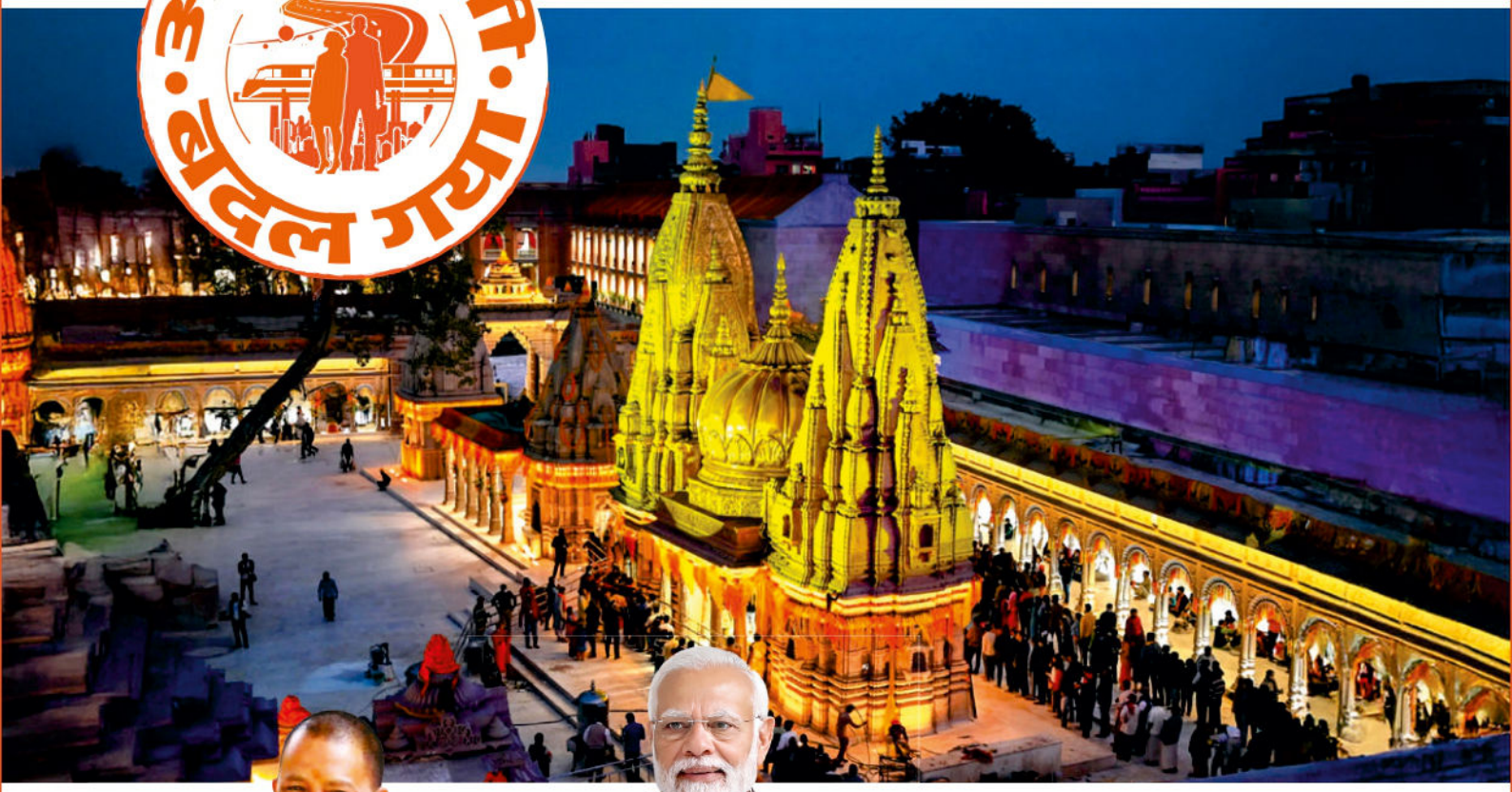
काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

नवनिर्माण के ९ वर्ष

पहले भय का परिवेश
आज पर्यटन प्रदेश

अपना यूपी बदल गया





2017 में
23.7 करोड़ पर्यटक

2025 में
156 करोड़+
पर्यटक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP